सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 251, नई दिल्ली । गुरुवार, 21 नवम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अनुशासन एक ऐसा तरीका है जो उसमें कामयाब हो गया, वो हर कार्य में जीत सकता है।

03 दिल्ली सरकार द्वारा मृतक के परिवार को 10 की सहायता राशि...
06 कृत्रिम बुद्धि का बढ़ता प्रभाव
08 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु दिसंबर में ओडिशा की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं

मुख्यमंत्री आतिशी से डीटीसी के हड़ताली कर्मचारियों की बात के बाद निर्णय...

मंगलवार की सीएम द्वारा बैठक में दिए गए दिशा निर्देश का अनुसार दिल्ली परिवहन निगम ने आदेश कर सरोजनी नगर डिपो की सभी महिलाओं को उनके पुराने दिल्ली परिवहन निगम के डिपो में वापिस भेज दिया। इसे के साथ दिल्ली में बना पहला महिला डिपो बंद हो कर वापिस आप डिपो की तरह काम करेगा। इसी के साथ दिल्ली में डीटीसी की स्ट्राइक भी खत्म हो गई और जनता को डीटीसी/ क्लस्टर की बसे समयानुसार उपलब्ध होनी शुरू हो गई। *- संजय बाटला*

दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय 3 लेवल, ए विंग, दिल्ली सचिवालय

बैठक के मिनट

दिनांक 19-11-2024

19.11.20.24 को शाम 7 बजे दिल्ली सचिवालय के कॉन्फ्रेंस बीम में डीटीसी के कर्मचारियों, जिसमें ड्राइवर भी शामिल थे, के साथ माननीय मुख्यमंत्री की एक बैठक आयोजित की गई। डीटीसी कर्मचारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दसवीं बार चर्चा की गई। माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि

1. पिंक बस डिपो में कार्यरत डीटीसी कर्मचारियों को जारी किए गए सेवा समाप्ति पत्र उनके वापस ड्यूटी पर आते ही वापस ले लिए जाएंगे

2. पिंक बस डिपो में कार्यरत महिला डीटीसी कर्मचारियों को उनके अनुरोध के अनुसार उनके मूल डिपो में वापस स्थानांतरित किया जाएगा।

3. अन्य कर्मचारी जिनके स्थानांतरण के लिए सामान्य अनुरोध हैं, उन्हें यथासंभव उनके निवास के निकटतम डिपो में समायोजित किया जाएगा।

4. संविदा चालकों और परिचालकों को मार्च, 2025 के बाद भी जारी रखने के लिए नीति पेश की जाएगी।

5. डीटीसी बोर्ड/मंत्रिपरिषद के स्तर पर सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नीतिगत निर्णय लिया जाएगा, जिसे सेवा मास्टर होने के कारण माननीय उपराज्यपाल को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।

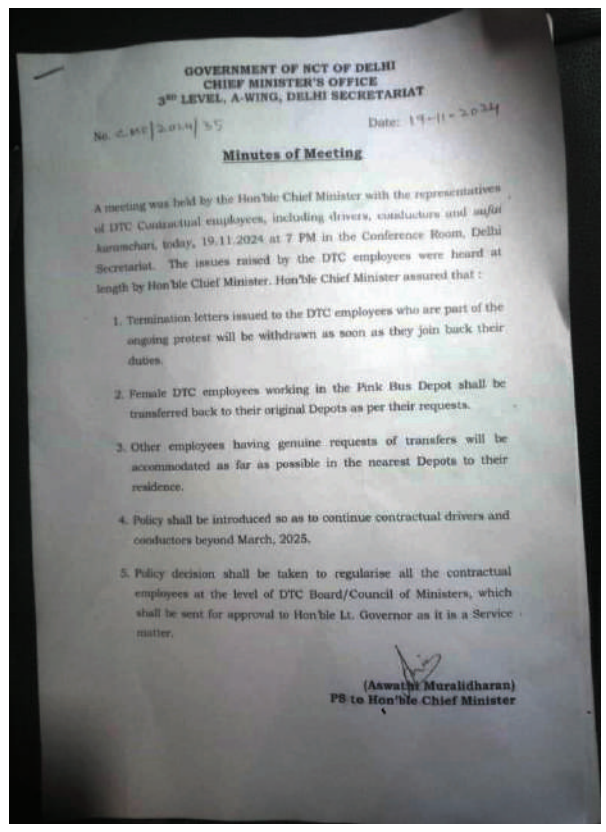

(अश्वती मुरलीधरन) माननीय मुख्यमंत्री के निजी सचिव

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
CHIEF MINISTER'S OFFICE
3RD LEVEL, A-WING, DELHI SECRETARIAT

No. CMO/2024/35 Date: 19-11-2024

Minutes of Meeting

A meeting was held by the Hon'ble Chief Minister with the representatives of DTC Contractual employees, including drivers, conductors and safai karamchari, today, 19.11.2024 at 7 PM in the Conference Room, Delhi Secretariat. The issues raised by the DTC employees were heard at length by Hon'ble Chief Minister. Hon'ble Chief Minister assured that :

1. Termination letters issued to the DTC employees who are part of the ongoing protest will be withdrawn as soon as they join back their duties.
2. Female DTC employees working in the Pink Bus Depot shall be transferred back to their original Depots as per their requests.
3. Other employees having genuine requests of transfers will be accommodated as far as possible in the nearest Depots to their residence.
4. Policy shall be introduced so as to continue contractual drivers and conductors beyond March, 2025.
5. Policy decision shall be taken to regularise all the contractual employees at the level of DTC Board/Council of Ministers, which shall be sent for approval to Hon'ble Lt. Governor as it is a Service matter.

(Aswathi Muralidharan)
PS to Hon'ble Chief Minister

बड़ी है तैयारी: ट्रेनों में उमड़ने वाली भीड़ की राह होगी आसान, एक लाख अतिरिक्त यात्री रोजाना कर सकेंगे यात्रा

रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार साधारण श्रेणी वाले कोच निर्माण पर फोकस किया जा रहा है। अगले महीने से नियमित ट्रेनों में 370 नया कोच लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा।

नई दिल्ली। ट्रेनों में उमड़ने वाली भीड़ की राह अब जल्द ही आसान होगी। रेलवे इसे लेकर एक एक्शन प्लान तैयार किया है ताकि आम लोगों की सफर को सुविधायुक्त बनाया जा सके। इसके तहत ज्यादा से ज्यादा संख्या में अनारक्षित डिब्बों का निर्माण किया जा रहा है। जिसे नियमित ट्रेनों में जोड़कर चलाया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग प्रतिदिन सफर कर सकेंगे। अगले महीने तक 1000 नया कोच ट्रेनों में जुड़ेगा। इससे एक लाख अतिरिक्त यात्री प्रतिदिन यात्रा कर सकेंगे। रेलवे के इस पहल से कुंभ और होली त्योहार के दौरान उमड़ने वाली भीड़ की राह आसान हो सकेगी।

आम यात्रियों की राह अब जल्द ही ट्रेनों से आसान होगी। सड़क या अन्य परिवहन के माध्यम से उन्हें लंबी-लंबी दूरी तय करने की मजबूरी नहीं होगी। इसके लिए रेलवे बड़े पैमाने पर नये डिजाइन वाला अनारक्षित कोच का निर्माण कर रहा है।

रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार साधारण श्रेणी वाले कोच निर्माण पर फोकस किया जा रहा है। अगले महीने से नियमित ट्रेनों में 370 नया कोच लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि एक लाख अतिरिक्त यात्री प्रतिदिन नये अनारक्षित कोच में यात्रा कर सकेंगे।

अधिकारियों के अनुसार नॉन एसी कोच भी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। चेन्नई व कपूरथला रेल कोच फैक्टरी समेत अन्य कोच फैक्टरी में कोच का निर्माण किया जा रहा है। जिसे पूरे देश में चलने वाली ट्रेनों में जोड़कर चलाया जाएगा। कुंभ और होली के दौरान भीड़ बढ़ी तो इन्हीं कोच को जोड़कर अनारक्षित ट्रेन चला दी जाएगी।

इस नीति के तहत रेलवे ने अगले दो साल में 10 हजार साधारण श्रेणी वाले कोच निर्माण कराने जा रहा है। इसका फायदा यह होगा कि आठ लाख यात्री प्रतिदिन नियमित ट्रेनों के साधारण कोच में यात्रा कर सकेंगे। दरअसल बीते दिनों में त्योहार के दौरान चार करोड़ अतिरिक्त यात्रियों की भीड़ उमड़ने से सबक लेते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में अनारक्षित

दिल्ली में वाहन चालक रहे सावधान! परिवहन निगम चला रहा है यह अभियान

दिल्ली-एनसीआर इलाके में वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली परिवहन निगम ने दो हजार से ज्यादा वाहनों को जब्त किया है.

नई दिल्ली। सर्दियां शुरू होते ही दिल्ली-एनसीआर इलाके में वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ने लगी है. ऐसे में दिल्ली परिवहन निगम ने खराब वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए अभियान चलाया. पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार निगम ने इस अभियान के तहत 1 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच 2,234 पुराने वाहन जब्त किए हैं.

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जब्त किए गए वाहनों में 260 डीजल चार पहिया वाहन शामिल हैं, जो 10 साल से अधिक पुराने हैं. इसके अलावा 1,156 दोपहिया वाहन और 818 पेट्रोल तीन और चार पहिया वाहन हैं, जो 15 साल से अधिक पुराने हैं. जानकारी के अनुसार यह अभियान दिसंबर तक चलाया जाएगा, जो पर्यावरण नियमों को लागू करने और उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़े अभियान का हिस्सा है.

इस अभियान के साथ-साथ परिवहन विभाग ने जब्त वाहनों को स्क्रैप करने, वापस लेने या बेचने की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है. यह प्लेटफॉर्म प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए बनाया गया है, जो मालिकों को वाहनों के प्रबंधन के लिए एक स्पष्ट एसओपी प्रदान करता है.

बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता खराब होने के साथ, ऑड-ईवन योजना एक और उपाय है, जिसके वापस आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं. यह योजना पहली बार 2016 में लागू की गई था और उसके बाद से लगभग हर साल, यह योजना सड़कों पर निजी स्वामित्व वाली कारों की संख्या को सीमित करने के लिए लागू की जाती है।

इस योजना के तहत विषम अंक पर समाप्त होने वाले लाइसेंस प्लेट वाले वाहनों को विषम तिथियों पर चलने की अनुमति दी जाती है, और सम अंक पर समाप्त होने वाले वाहनों को सम तिथियों पर चलने की अनुमति दी जाती है. हालांकि, इस योजना के तहत CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट दी गई थी.

इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने पहले ही BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल प्रमाणित कमर्शियल और निजी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है. इन उपायों से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने में मदद मिलेगी।

असली विंटेज कारों को स्क्रैप कराने के लिए जब्त न करें, दिल्ली एलजी का अधिकारियों को निर्देश

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने परिवहन विभाग और नगर निकायों को निर्देश दिया है कि वे अपने प्रवर्तन दलों को शहर में विंटेज कार मालिकों को कथित रूप से परेशान करने से रोकें।

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने परिवहन विभाग और नगर निकायों को निर्देश दिया है कि वे अपने प्रवर्तन दलों को शहर में विंटेज कार मालिकों को कथित रूप से परेशान करने से रोकें। उपराज्यपाल कार्यालय के एक नोट में यह कहा गया है।

हेरिटेज मोटरिंग क्लब ऑफ इंडिया ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक ज्ञापन में शिकायत की है कि अधिकारियों द्वारा स्क्रैपिंग के लिए विंटेज वाहनों को जब्त किया जा रहा है।

परिवहन विभाग और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की प्रवर्तन टीमें 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को स्क्रैपिंग के लिए जब्त करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में अपने आदेश में दिल्ली में ऐसे एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों के चलने पर रोक लगा दी थी।

हेरिटेज मोटरिंग क्लब ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए ज्ञापन पर कार्रवाई करते हुए, एलजी ने अपने सचिवालय से उचित निर्देश जारी करने को कहा। ज्ञापन में बताया गया था कि उनके वाहनों को अधिकारियों द्वारा जब्त किया जा रहा है और इस संबंध में स्पष्टीकरण आदेश का अनुरोध किया गया है।

नोट में कहा गया है, ₹एलजी ने विंटेज कार मालिकों द्वारा सामना किए जा रहे उत्पीड़न पर ध्यान दिया है और परिवहन और एमसीडी को निर्देश दिया है कि वे स्क्रैपिंग के लिए वास्तविक विंटेज वाहनों को जब्त न करें।₹

उपराज्यपाल सचिवालय ने दिल्ली सरकार के परिवहन आयुक्त और एमसीडी आयुक्त को चिट्ठी लिखकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उनकी प्रवर्तन शाखाएं इस संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचनाओं के तहत पंजीकृत वाहनों के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई करने से बचें।

एलजी सचिवालय ने कहा कि 15 जुलाई, 2021 को MoRTH द्वारा जारी अधिसूचना में 50 वर्ष या उससे अधिक पुराने वाहनों को विंटेज वाहनों के रूप में पंजीकरण करने का प्रावधान किया गया है।

MoRTH की अधिसूचना के आधार पर, दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने 2 दिसंबर, 2021 को विंटेज वाहनों के लिए सामान्य सीरीज DLVA (डीएलवीए) के आवंटन का आदेश दिया। आगे के आदेशों में, विभाग ने विंटेज मोटर वाहन के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन और जारी करने की प्रक्रिया के बारे में बताया।

नोट में आगे कहा गया है कि यहां तक कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने भी 18 दिसंबर, 2017 को अपने आदेश में निर्देश दिया था कि ₹शर्तों की पूर्ति के अधीन एंटीक कारों/वाहनों को विंटेज वाहनों के रूप में

बिहार में पांच हाईवे प्रोजेक्ट को मिली हरी झंडी, ADB की मदद से जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य

बिहार में बाणगंगा-भिंदस, आरा-एकाउना, छपरा-गुथनी, हथौड़ी-अतरार और असरगंज-धोरैया में राज्य उच्च पथ (एसएच) के निर्माण को लेकर बुधवार को पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह और एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक हुई.

नई दिल्ली। बिहार में बाणगंगा-भिंदस, आरा-एकाउना, छपरा-गुथनी, हथौड़ी-अतरार और असरगंज-धोरैया में राज्य उच्च पथ (SH) के निर्माण को लेकर बुधवार को पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह और एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक हुई. बैठक का मुख्य उद्देश्य परियोजनाओं में आ रही जमीन अधिग्रहण और फॉरेस्ट क्लीयरेंस से जुड़ी समस्याओं को हल करना था.

अपर मुख्य सचिव का आश्वासन

अपर मुख्य सचिव ने एडीबी के प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि इन समस्याओं का समाधान तेजी से किया जाएगा. उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग और निगम त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ताकि परियोजना पर काम समय पर शुरू हो सके.

एडीबी की वित्तीय सहायता और लोन प्रक्रिया

इन सड़कों का निर्माण एडीबी की वित्तीय सहायता से किया जा रहा है। बैठक में बताया गया कि परियोजना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति पहले ही सरकार द्वारा दी जा चुकी है. एडीबी का प्रतिनिधिमंडल इन परियोजनाओं की रिपोर्ट अपने मनीला मुख्यालय में एडीबी प्रेसिडेंट को सौंपेगा। इसके बाद लोन की राशि जारी की जाएगी.

योजना पर तेजी से काम का निर्देश

BSRDCL के प्रबंध निदेशक शीर्षत कपिल अशोक ने सभी अभियंताओं को एडीबी की लोन शर्तों के अनुसार काम करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि किसी भी प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता होने पर तुरंत उनके संज्ञान में लाया जाए ताकि परियोजना को तय समय पर शुरू किया जा सके.

बैठक में प्रमुख अधिकारियों की भागीदारी

बैठक में विभागीय सचिव बी कार्तिकेय धनजी, BSRDCL के मुख्य महाप्रबंधक प्रवीण चंद्र गुप्ता, और एडीबी के प्रतिनिधि यिदान लुओ, जागीर कुमार, मारिया आइरिस, मारिया लॉरिन, आशुतोष कुमार सिंह और असद इंतखाब नायर समेत कई अधिकारी मौजूद थे.

परियोजना से राज्य को उम्मीदें

राज्य में इन एसएच परियोजनाओं के पूरा होने से सड़क संपर्क और यातायात में सुधार की उम्मीद है. यह परियोजनाएं न केवल बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करेंगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देंगी. एडीबी के सहयोग से इन सड़कों का निर्माण बिहार के विकास में एक बड़ा कदम साबित होगा.

केरल की यह अद्भुत जगह देख भूल जाएंगे मुन्नार और वायनाड, पार्टनर के साथ बिता आएं क्वालिटी टाइम

मुन्नार में मौजूद रानीपुरम एक ऐसी जगह है, जिसकी खूबसूरती देख यकीनन आप वायनाड और मुन्नार जैसे फेमस हिल स्टेशनों को भूल जाएंगे। ऐसे में अगर आप भी केरल घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है।

अक्सर लोग छुट्टी मिलते ही घूमने का प्लान बना लेते हैं। वैसे तो हमारे देश में घूमने के लिहाज से कई बेहतरीन जगहें मौजूद हैं। लेकिन जब दक्षिण भारत के किसी शानदार जगह पर घूमने की बात होती है, तो लोग सबसे पहले केरल का नाम लेते हैं। केरल विश्व प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है। अरब सागर के तट पर स्थित केरल में एक से एक बेहतरीन जगहें हैं। यहां पर न सिर्फ देश से बल्कि विदेशी लोग भी घूमने के लिए पहुंचते हैं।

वहीं मुन्नार में मौजूद रानीपुरम एक ऐसी जगह है, जिसकी खूबसूरती देख यकीनन आप वायनाड और मुन्नार जैसे फेमस हिल स्टेशनों को भूल जाएंगे। ऐसे में अगर आप भी केरल घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको रानीपुरम की खासियत और यहां मौजूद कुछ शानदार जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं।

रानीपुरम

केरल के कासरगोड जिले में स्थित रानीपुरम एक बेहद खूबसूरत, अद्भुत और शानदार हिल स्टेशन है। यह केरल के छिपे हुए खजानों में से एक माना जाता है। यह ऊंचे-ऊंचे पहाड़, आकर्षक नजारे और सदाबहार वनस्पतियों के लिए पूरे राज्य में फेमस है। रानीपुरम का शांत और सुकून भरा वातावरण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आप यहां पर परिवार या पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं।

घूमने की बेस्ट जगहें

बता दें कि रानीपुरम में कई बेहतरीन और अद्भुत जगहें मौजूद हैं, जहां पर घूमने के बाद आप मुन्नार और वायनाड जैसी जगहों को यकीनन भूल जाएंगे।

वाइल्डलाइफ सेंक्चुअरी

अगर रानीपुरम में किसी शानदार और मनमोहक जगह घूमने की बात की जाए, तो रानीपुरम वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी का नाम सबसे पहले आता है। समुद्र तल से करीब 750 मीटर पर मौजूद यह जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए हसीन जन्नत के समान है।

रानीपुरम वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी सिर्फ केरल ही नहीं बल्कि कर्नाटक की खूबसूरती को बढ़ाता है। यह कर्नाटक की सीमा पर मौजूद है और आप यहां पर बाघ, हाथी, जंगली सुअर, जंगती बंदर और हिरण आदि कई जानवरों को बेहद करीब से देख सकते हैं।

रानीपुरम ट्रेक

यह ट्रेक किसी हसीन ख्वाब से कम नहीं हैं। क्योंकि रानीपुरम ट्रेक कासरगोड की सबसे ऊंची चोटी है। जब आप इस ट्रेक पर जाते हैं, तो आपको अपने चारों ओर लुभावने और मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं। इस ट्रेक की हरियाली भी पर्यटकों को खूब लुभाती है। चोटी की ऊंचाई से आसपास का नजारा बेहद खूबसूरत लगता है।

मालोम गांव

बता दें कि रानीपुरम से कुछ ही दूरी पर मालोम गांव है। यह गांव प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। यहां पर ऊंचे-ऊंचे पहाड़, चाय और कॉफ़ी के बागानों के बीच मौजूद यह गांव खूबसूरती का खजाना माना जाता है। आप मालोम गांव में केरल की पारंपरिक और सांस्कृतिक रिवाजों को करीब से देख सकते हैं। इसके साथ ही चाय और कॉफी के बागानों की फोटोग्राफी भी कर सकते हैं।

बिना सर्जरी के भी चेहरे की त्वचा रहेगी टाइट, यहां देखिए स्किन टाइटनिंग के नॉन सर्जिकल ऑप्शन

अगर आप भी चाहती हैं कि स्किन टाइट लगे और आप लंबे समय तक यंग दिखती रहें, तो आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको स्किन टाइट रखने के लिए कुछ नॉन-सर्जिकल उपायों के बारे में बता रहे हैं।

बढ़ती उम्र के साथ ही चेहरे पर झुर्रियां आना और त्वचा का ढीला पड़ना आम बात है। त्वचा ढीली पड़ने पर चेहरे की सुंदरता कम होने लगती है। ऐसे में महिलाएं स्किन को टाइट रखने के लिए कई तरह के उपाय अपनाती हैं। हालांकि कई बार सही जानकारी न होने पर लोग ऐसे टिप्स भी अपनाने लगते हैं, जिनके काफी ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो वहीं बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्किन टाइट रखने के लिए सर्जरी ही एकमात्र ऑप्शन है, जबकि ऐसा नहीं है।

बता दें कि त्वचा से फाइन लाइन्स को दूर रखने और स्किन को टाइट रखने के कई नॉन सर्जिकल ऑप्शन भी मौजूद हैं। इन ट्रीटमेंट्स की मदद से चेहरे की स्किन यंग नजर आने लगती है। ऐसे में अगर आप भी चाहती हैं कि स्किन टाइट लगे और आप लंबे समय तक यंग दिखती रहें, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको स्किन टाइट रखने के लिए कुछ नॉन-सर्जिकल उपायों के बारे में बता रहे हैं।

अल्ट्रासाउंड थेरेपी

अल्ट्रासाउंड थेरेपी स्किन की डीपर लेयर्स में किया जाता है। यह कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है और त्वचा को टाइट रखता है।

यह थेरेपी समय के साथ त्वचा को ढीली नहीं पड़ने देती है। त्वचा को टाइट रखने का यह नॉन-इनवेसिव ट्रीटमेंट काफी लोकप्रिय है।

रेडियोफ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट

स्किन की गहरी परतों में एनर्जी पहुंचाकर यह ट्रीटमेंट किया जाता है। बता दें कि यह ट्रीटमेंट कोलेजन के प्रोडक्शन और इलास्टिन को बढ़ाता है। वहीं थर्मेज का इस्तेमाल सैगिंग को कम करने और स्किन टेक्स्चर को सही करने के लिए किया जाता है।

यह ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए अच्छा माना जाता है, जो बिना किसी सर्जरी के अपनी स्किन को टाइट करना चाहते हैं।

लेजर ट्रीटमेंट

फ्रैक्शनल लेजर थेरेपी भी कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे स्किन टाइट होती है। इसमें CO_2 और एर्बियम लेजर काफी पॉपुलर हैं। यह दोनों स्किन को टाइट रखने के अलावा अपियरेंस को भी ठीक करने में मदद करते हैं।

माइक्रोनीडलिंग

माइक्रोनीडलिंग में स्किन में छोटे-छोटे नीडल्स से माइक्रो-इंजरी की जाती है। इस प्रक्रिया से कोलेजन और इलास्टिन प्रोडक्शन बढ़ता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन टाइट और स्मूद होती है। इसके साथ ही यह प्रोसेस सीरम के अवशोषण को बढ़ाता है और उसको अधिक प्रभावी बनाता है।

केमिकल पील

केमिकल पील त्वचा की बाहरी परत को एक्सफोलिएट करने के साथ टेक्चर में सुधार करता है, जिससे त्वचा टाइट होता है। इसमें लाइट पील से लेकर डीप पील तक का ऑप्शन उपलब्ध होता है। जहां लाइट पील स्किन को रिफ्रेश करता है, तो वहीं डीप पील स्किन की गहरी परतों पर बेहतर तरीके से काम करता है।

क्रायोलिपोलिसिस

यह आमतौर पर फैट को कम करता है। इसका ब्रांड नाम कूलस्कल्पिंग है। क्रायोलिपोलिसिस ट्रीटेड एरिया में स्किन को टाइट करता है। साथ ही प्रोसिजर फैट सेल्स को ठंडा करता है और फैट कम करके त्वचा को टाइट बनाता है।

क्रीम और सीरम

अगर आप अपने फेस पर दुनियाभर का ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहती हैं, तो आप स्किन पर क्रीम और सीरम का यूज कर सकती हैं। इसमें टिनॉइड्स, पेप्टाइड्स और ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। ऐसे में क्रीम और सीरम का लगातार इस्तेमाल करने से स्किन में कसाव आता है।

LED लाइट थेरेपी

LED लाइट थेरेपी का इस्तेमाल त्वचा में कोलेजन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें एक लेजर से विशेष प्रकार की रोशनी का उपयोग किया जाता है। इसकी मदद से स्किन टोन में सुधार आता है और चेहरे की महीन लकीरों को बी कम करने में सहायता मिलती है। साथ ही यह आपकी त्वचा को किसी भी तरह का नुकसान भी नहीं पहुंचाता है।

प्रेग्नेंसी में मां और बच्चे दोनों को प्रभावित कर सकता है गाइनेकोलॉजिकल इंफ़ेक्शन, जानिए बचाव के तरीके

प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं को स्त्रीरोग संबंधी संक्रमण होने का खतरा भी बढ़ जाता है। यह न सिर्फ महिलाओं बल्कि उनके गर्भ में पलने वाले बच्चे की सेहत पर भी बुरा असर डाल सकता है।

गर्भावस्था के शुरूआती दिनों से ही महिलाओं को कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। प्रेग्नेंसी को तीन तिमाही में बांटा जाता है। इन तीन तिमाही के दौरान महिलाओं को अलग-अलग लक्षण महसूस होते हैं। इस दौरान महिलाओं के शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं, जो समस्याओं का कारण माने जाते हैं। वहीं प्रेग्नेंसी के समय होने वाले बदलावों जैसे मोटापा और वजन बढ़ने आदि से महिलाओं को उठने-चलने में परेशानी होने लगती है।

प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं को स्त्रीरोग संबंधी संक्रमण होने का खतरा भी बढ़ जाता है। यह न सिर्फ महिलाओं बल्कि उनके गर्भ में पलने वाले बच्चे की सेहत पर भी बुरा असर डाल सकता है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए आपको बताने जा रहे हैं कि प्रेग्नेंसी में गाइनाक्लॉजिस्ट इंफेक्शन के क्या कारण होते हैं और इससे किस तरह से बचाव किया जाना चाहिए।

गर्भावस्था में स्त्रीरोग संबंधी संक्रमणों के कारण

बैक्टीरियल वेजिनोसिस

बैक्टीरियल वेजिनोसिस इंफेक्शन तब होता है, जब योनि में सामान्य रूप से पाई जाने वाली बैक्टीरिया में असंतुलन पाया जाता है। प्रेग्नेंसी के दौरान हार्मोनल बदलाव और इम्यून सिस्टम में कमजोरी होने की वजह से महिलाएं वेजिनोसिस के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाती हैं। यह इंफेक्शन समय से पहले यानी की प्रीटर्म डिलीवरी और गर्भाशय के अंदर संक्रमण का कारण बन सकता है।

फंगल इंफेक्शन

प्रेग्नेंसी के समय हार्मोनल बदलाव और शुगर के स्तर में वृद्धि होती है। जिसके कारण योनि में यीस्ट की अत्यधिक वृद्धि हो सकती है। इससे भी प्रेग्नेंट महिलाओं को फंगल इंफेक्शन का खतरा हो सकता है। यह इंफेक्शन जलन, खुजली और सफेद रंग का गाढ़ा स्त्राव पैदा कर सकता है। वहीं अगर इसका समय पर इलाज नहीं किया जाए, तो यह गर्भाशय और गर्भ में पलने वाले शिशु दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।

यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन

बता दें कि गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय बढ़ता है, जिसका दबाव ब्लैडर पर पड़ता है। जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। वहीं UTI गर्भाशय के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा सकता है, जोकि समय से पहले डिलीवरी का कारण बन सकता है। वहीं यह संक्रमण किडनी तक भी फैल सकता है। जो न सिर्फ मां बल्कि बच्चे के स्वास्थ्य के लिए समस्याएं पैदा कर सकता है।

अन्य संक्रमण का खतरा

सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन्स

ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस

बचाव

प्रेग्नेंसी के दौरान संक्रमण से बचने के लिए महिलाओं को योनि की साफ-सफाई पर बहुत ध्यान देना चाहिए। इसके लिए आप पानी और माइल्ड साबुन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं।

प्रेग्नेंसी में संतुलित और पौष्टिक आहार लेना चाहिए। क्योंकि इससे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और इंफेक्शन से बचाव होता है।

प्रेग्नेंसी के दौरान सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन्स से बचाव के लिए फिजिकल इंटिमेसी में सावधानी बरतनी चाहिए।

इस दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से भी आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन्स का खतरा कम होता है।

मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन वाला मोटो G75 5G लॉन्च, जानें डिजाइन, स्पेसिफिकेशन्स और कीमत

Moto G75 5G एक ऐसा स्मार्टफोन है जो मजबूत डिज़ाइन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और बेहतर कैमरा फीचर्स के साथ आता है। यह फोन उन यूजर्स के लिए परफेक्ट है जो एक प्रीमियम और भरोसेमंद डिवाइस की तलाश में हैं।

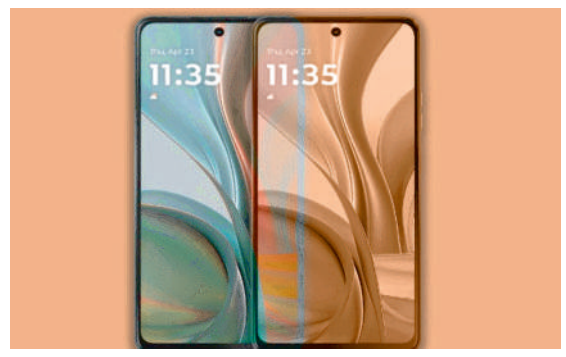

Moto G75 5G, मोटोरोला की जी सीरीज का नया स्मार्टफोन, यूरोप में लॉन्च कर दिया गया है। यह फोन अपने दमदार फीचर्स और मजबूत डिजाइन के साथ बाजार में चर्चा में है। Moto G75 5G एक ऐसा स्मार्टफोन है जो मजबूत डिज़ाइन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और बेहतर कैमरा फीचर्स के साथ आता है। यह फोन उन यूजर्स के लिए परफेक्ट है जो एक प्रीमियम और भरोसेमंद डिवाइस की तलाश में हैं। आइए जानते हैं इस फोन की खासियत, डिज़ाइन, स्पेसिफिकेशन्स और कीमत से जुड़ी हर जानकारी।

डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी

Moto G75 5G का डिज़ाइन इसे अन्य स्मार्टफोन्स से अलग बनाता है। फोन में पॉलीकार्बोनेट चेसिस के साथ बॉक्सी डिज़ाइन है, जो इसे प्रीमियम लुक देता है।

– डिस्प्ले: यह 6.78 इंच की FHD+ LCD डिस्प्ले के साथ आता है। डिस्प्ले में 120Hz रिफ्रेश रेट, 240Hz टच सैंपलिंग रेट, और 1,000 निट्स तक ब्राइटनेस का सपोर्ट है।

– सुरक्षा: फोन को गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है।

– कलर ऑप्शन: इसे तीन कलर वेरिएंट में पेश किया गया है:

Charcoal Grey (मैट फिनिश)

Succulent Green (वीगन लेदर फिनिश)

Aqua Blue

फोन को पानी और धूल से सुरक्षित रखने के लिए IP68 रेटिंग दी गई है। इसके अलावा, इसे MIL-STD-810H मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन भी प्राप्त है, जो इसे कठिन परिस्थितियों में भी मजबूती प्रदान करता है।

हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर

Moto G75 5G में लेटेस्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह अपने सेगमेंट में एक परफेक्ट स्मार्टफोन बनता है।

– प्रोसेसर: यह दुनिया का पहला फोन है जो क्वालकॉम Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेट पर चलता है। यह 4nm आर्किटेक्चर पर आधारित है, जिससे बेहतर परफॉर्मेंस और पावर इफिशियंसी मिलती है।

– सॉफ्टवेयर: फोन में Android 14 बेस्ड MyUX स्किन का सपोर्ट है। मोटोरोला ने 5 साल तक OS अपग्रेड और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है।

– मेमोरी और स्टोरेज:

8GB LPDDR4x रैम

256GB UFS 2.2 इंटरनल स्टोरेज

8GB तक वर्चुअल रैम

स्टोरेज को मेमोरी कार्ड के जरिए बढ़ाने का विकल्प भी उपलब्ध है।

कैमरा फीचर्स

Moto G75 5G अपने कैमरा सेटअप के लिए भी आकर्षक है।

– रियर कैमरा:

- 50MP प्राइमरी कैमरा (सोनी LYTIA 600 सेंसर)
- ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ
- 8MP का अल्ट्रावाइड कैमरा

फ्रंट कैमरा:

- 16MP का सेल्फी शूटर

कैमरा फीचर्स की वजह से यह फोन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन सकता है।

बैटरी और ऑडियो

Moto G75 5G में लंबी बैटरी लाइफ और शानदार ऑडियो का भी ख्याल रखा गया है।

- बैटरी: 5,000mAh की दमदार बैटरी के साथ यह फोन आता है, जो दिनभर का बैकअप देने में सक्षम है।
- ऑडियो: इसमें डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं, जो बेहतरीन साउंड क्वालिटी प्रदान करते हैं।

कीमत और उपलब्धता

Moto G75 5G को फिलहाल यूरोप में लॉन्च किया गया है। इसकी कीमत CZK 8,999 (लगभग 33,317 रुपये) रखी गई है। कंपनी ने घोषणा की है कि यह फोन जल्द ही चीन और भारत जैसे मार्केट्स में भी लॉन्च किया जाएगा। भारत में इसकी लॉन्च डेट और कीमत के बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।

क्यों खरीदें Moto G75 5G ?

1. मजबूत डिजाइन: MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन और IP68 रेटिंग।
2. दमदार प्रोसेसर: क्वालकॉम Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेट।
3. लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट: 5 साल के OS और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट।
4. प्रीमियम फीचर्स: 120Hz डिस्प्ले, डॉल्बी एटमॉस ऑडियो और 50MP का OIS कैमरा।

रेडमी A4 5G भारत में होगा लॉन्च, शुरुआती कीमत 8,499 रुपये, जानें पूरी डिटेल

फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट दिया गया है। फोन 4nm स्नैपड्रैगन 4s Gen 2 चिपसेट के साथ आएगा। पावर बैकअप के लिए फोन में 5160mAh की बैटरी दी गई है। साथ ही 18W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। फोन एंड्रॉइड 14 बेस्ड कंपनी के HyperOS स्किन पर काम करेगा।

Redmi A4 5G स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। ये कंपनी का अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन है। फोन को 8,499 रुपये की शुरुआती कीमत में पेश किया गया है। ये हैंडसेट 50 मेगापिक्सल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। अगर डिस्प्ले की बात की जाए, तो बजट सेगमेंट के बावजूद फोन को 6.88 इंच की बड़ी एलईडी स्क्रीन के साथ पेश किया गया है। फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट दिया गया है। फोन 4nm स्नैपड्रैगन 4s Gen 2 चिपसेट के साथ आएगा। पावर बैकअप के लिए फोन में 5160mAh की बैटरी दी गई है। साथ ही 18W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। फोन एंड्रॉइड 14 बेस्ड कंपनी के HyperOS स्किन पर काम करेगा।

कीमत और उपलब्धता

फोने के 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट को भारत में 8,499 रुपये की शुरुआती कीमत में पेश किया गया है। इसके अलावा 4GB रैम और 128GB स्टोरेज ऑप्शन को 9,499 रुपये में पेश किया गया है। फोन को स्पार्कल पर्पल और स्टेयरी ब्लैक कलर ऑप्श में आता है। फोन की ब्रिकी 27 नवंबर से शुरू होगी। फोन को कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदा जा सकेगा।

वहीं इस फोन 6.88 इंच HD+ एलसीडी डिस्प्ले में आएगा। इसका रेजोल्यूशन 720X1640 पिक्सल होगा फोन 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आएगा। फोन में 4nm Snapdragon 4s Gen 2 chip चिपसेट दिया गया है। जिसे 4GB LPDDR4X रैम सपोर्ट दिया जाएगा। फोन ड्यूल सिम सपोर्ट के साथ आएगा। Redmi A4 5G स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 बेस्ड HyperOS पर काम करेगा। फोन दो साल सॉफ्टवेयर अपडेट और चार साल सिक्योरिटी अपडेट के साथ आएगा।

प्राइवेट संस्थानों में भी वर्क फ्रॉम होम के लिए निर्देश जारी किया गया है - गोपाल राय

सुषमा रानी

नई दिल्ली, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार वायु प्रदूषण को कम करने और जनता को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार के फैसले की जानकारी साझा करते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि प्रदूषण कम करने के लिए ग्रेप-4 के प्रावधानों के तहत सरकार ने कई कदम उठाये हैं। उसी क्रम में बुधवार को दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम का निर्णय लिया है।

उन्होंने बताया कि कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता से खुलेंगे, जबकि 50 प्रतिशत कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेगें। आवश्यक सेवाएं वाले विभाग में वर्क फ्रॉम होम लागू नहीं होगा। इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए पर्यावरण विभाग , सामान्य प्रशासन विभाग और औद्योगिक संघ फिक्की , एसोचेम और सीआईआई के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली सचिवालय में की। उन्होंने कहा कि प्राइवेट संस्थानों के लिए भी 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम करने के लिए निर्देश जारी की जा रही है। प्राइवेट संस्थान अपना कार्यालय खोलने का समय 10.30 बजे या 11 बजे करें। साथ ही प्राइवेट कंपनी अपने कर्मचारी के लिए शटल बस सेवा शुरू करें। इसके लिए भी एडवाइजरी जारी की जा रही है।

गोपाल राय ने कहा कि पूरे उत्तर भारत में बदलते मौसम में प्रदूषण का प्रभाव मारक होता जा रहा है। पूरा उत्तर भारत गंभीर प्रदूषण की चपेट में है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए कई अभियान चला रही है जैसे एंटी डस्ट अभियान, बायो डीकम्पोज़र का छिड़काव, वृक्षारोपण अभियान, जागरूकता अभियान आदि। पूरे दिल्ली में सड़कों पर 200 मोबाइल एंटी स्मोग गन से पानी के छिड़काव का अभियान शुरू किया गया है। इसी क्रम में आज वर्क फ्रॉम होम का निर्णय लिया गया है। सरकारी के साथ साथ प्राइवेट कार्यालयों में भी वर्क फ्रॉम होम लागू होगा। अत्यावश्यक सेवाएं वाले विभाग में वर्क फ्रॉम होम लागू नहीं होगा, वह पूरी क्षमता के साथ काम करेगी।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रही है। आज ग्रेप-4 के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने के लिए उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग कर आदेश जारी किया गया है कि है ग्रेप-4 के नियमों को लागू करवाने में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी ।लेकिन पड़ोस के राज्यों को भी कड़े कदम उठाने होगें। तभी दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण को कम किया जा सकता है।

दिल्ली में 'दिल्ली सोलर पोर्टल' किया गया लांच

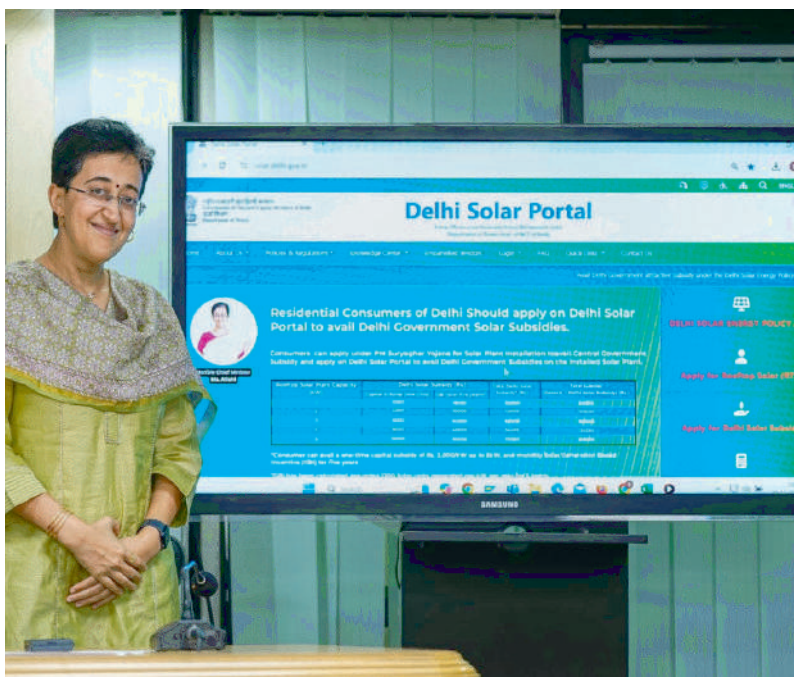

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली में आज बुधवार को 'दिल्ली सोलर पोर्टल' लांच किया गया है। लिहाजा, दिल्ली में जो भी लोग अपने घर की छतों पर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, ये पोर्टल उनके लिए एक सिंगल विंडो सोल्यूशन की तरह काम करेगा। वहीं, इस पोर्टल के ज़रिए लोग दिल्ली सोलर पॉलिसी के बारे में, सोलर पैनल लगाने वाले वेंडरों के बारे में, सरकार से मिलने वाली सब्सिडी और पैनल लगाने में आने वाले खर्चे के बारे में जान सकेंगे और घर बैठे सोलर पैनल भी लगवा सकेंगे। साथ ही लोग सब्सिडी और नेट मीटरिंग के लिए भी पोर्टल के ज़रिए ही आवेदन कर सकेंगे। वहीं, दिल्लीवासी दिल्ली सोलर पोर्टल solar.delhi.gov.in पर जाकर इस पॉलिसी का लाभ उठा सकते हैं।

केजरीवाल और आतिशी को आरोप-प्रत्यारोप बंद करके बताएं कि लोगों को वायु प्रदूषण से राहत देने के लिए आप सरकार ने क्या कदम उठाए हैं : देवेन्द्र यादव

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ सबसे प्रदूषित शहर भी है। अक्टूबर के शुरुआत से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है जिस पर अरविन्द केजरीवाल की रहनुमाई वाली आतिशी सरकार नियंत्रण पाने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। गैस चैंबर बनी राजधानी में स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होने के लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। दिल्ली का औसत एक्यूआई 460 है, जबकि अलीपुर में एक्यूआई 471, सोनिया विहार में एक्यूआई 470 आनंद विहार का एक्यूआई 466 के कारण खतरनाक प्रदूषण से प्रभावित लोगों के सवालों का जवाब आम आदमी पार्टी की सरकार के पास नही है, क्योंकि प्रदूषण रोकथाम के लिए कोई काम नही किया है।

यादव ने कहा कि पिछले 10 वर्ष केजरीवाल सरकार और अब आतिशी सरकार प्रदूषण के लिए कोई सकारात्मक काम करने की बजाय प्रदूषण के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराती है। चार बार संशोधन करके विंटर एक्शन प्लान इस वादे के साथ लागू किया, प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाऐंगे और रेड लाईट ऑन गाड़ी ऑफ, ''विशेष जल छिड़काव अभियान'' 70 एंटी स्मॉग गन, स्मॉग टावर, ''धूल प्रदूषण के विरुद्ध, पानी छिड़काव अभियान'' कई योजनाओं को लागू करने के बावजूद दिल्ली में ग्रेप 4 लागू करने की नौबत आ गई है। दिल्ली वालों की सांसो छीन रहे गंभीर होते प्रदूषण की जवाबदेही सरकार के पास नही है। उन्होंने कहा कि जब पंजाब में कांग्रेस सत्ता में थी तो केजरीवाल ने प्रदूषण के लिए पंजाब में पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराकर केवल नौटंकी करते थे परंतु अब आप पंजाब में उनकी सत्ता होने पर दिल्ली में प्रदूषण के लिए अन्य पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहराकर दिल्ली वालों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे है।

यादव ने कहा कि जब कांग्रेस दिल्ली की सत्ता में थी, तो वह हमेशा दिल्ली के विषयों पर जवाबदेह होती थी लेकिन केजरीवाल लोगों की समस्याओं को सुने बिना केवल लोगों की प्रदूषण, टूटी सड़कों और अन्य समस्याओं को दूर करने की बजाय अपने मन की बात कह रहे है। केजरीवाल ने पूरे 11 वर्ष लोगों के कल्याण, राजधानी में सुधार के लिए कोई ठोस काम करने की बजाय लोगों को झूठ बोलकर सिर्फ गुमराह करने का काम किया है। उन्हांने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी और उसे ग्रेप-4 लागू करने का निर्देश दिया था और पूछा था कि उसने प्रदूषण से निपटने के लिए पूरे साल में क्या कदम उठाए है। यह आश्यर्चजनक है कि सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट का कोई जवाब नहीं था।

उन्होंने कहा कि 1500 वर्ग किलोमीटर में फैली दिल्ली में वायु गुणवत्ता को मापने के लिए सिर्फ 40 स्टेशन नाकाफी है। लेकिन हकीकत यह भी है कि जिन क्षेत्रों में प्रदूषण अधिक होता है वहां एक्यूआई मापने वाले स्टेशन है। एक्यूआई स्टेशन 37 वर्ग किलोमीटर पर एक स्टेशन है। क्या हवा में गुणवत्ता है, कहना सरकार के प्रदूषण को रोकने वाले आंकड़ों में कितनी वास्तविकता है, यह कहना मुश्किल है? पर्यावरण विशेषज्ञ का कहना है कि एक स्टेशन से इतने बड़े क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाले इलाकों की पहचान नही हो सकती। मतलब साफ है आम आदमी पार्टी प्रदूषण रोकथाम के लिए सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है।

दिल्ली में सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड का लक्ष्य प्राथमिक लक्ष्य लोगों को बीमारियों, दुर्घटनाओं की रोकथाम और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मुद्दों पर शिक्षित करना

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली में सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है, मुफ्त चिकित्सा शिविर आयोजित करता है, और समुदाय के लिए अन्य मानवीय सहायता प्रदान करता है। इसका प्राथमिक लक्ष्य लोगों को बीमारियों, दुर्घटनाओं की रोकथाम और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मुद्दों पर शिक्षित करना है ताकि बीमारी के जोखिम को कम किया जा सके और जीवन बचाया जा सके। दिल्ली ब्रिगेड एक स्वैच्छिक संगठन है जिसमें कई स्वयंसेवक अधिकारी और सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। जहां भी कोई आपदा या आपात स्थिति होती है, वे मानवीय कार्यों का समर्थन करने के लिए प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में कार्य करते हैं।

अधिकारी और सदस्य विभिन्न शैक्षिक और अन्य संस्थान RWAs विभिन्न सामुदायिक वर्गों से आते हैं। सेन्ट जोहन एम्बुलेंस ब्रिगेड दिल्ली ने (ब्रिगेड इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कोर्स) 08 से 10 नवंबर 2024 तक कॉन्फ्रेंस हॉल कालीबाड़ी, सेक्टर - 7, आर के पुरम, नई दिल्ली- 22 में आयोजित किया गया था। सफदरजंग अस्पताल और सर गंगा राम अस्पताल एमएनई दिल्ली के आपातकालीन विभाग के प्रतिनिधि, एक सलाहकार मनोचिकित्सक अन्य सत्रों के संचालन के लिए संतोष मैडिकल कॉलेज के पूर्व सहायक

प्रोफेसर को आमंत्रित किया गया था।

यह प्रशिक्षण वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षकों के लिए आयोजित किया जाता है ताकि वे अपने डिवीजन और कोर को विकसित कर सकें, उनकी ताकत बढ़ा सकें, उनके ज्ञान और कौशल को बनाए रख सकें और अद्यतन कर सकें, और मानवता की सेवा करते हुए उनके प्रदर्शन में सुधार कर सकें और प्रति ब्रिगेड विनियमन पैरा 5 (ए), (ई) और (एफ)).

BLS (बेसिक लाइफ सपोर्ट) AHA (अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन) के निर्देशन में एक पूरे दिन का सत्र आयोजित किया, जिसके बाद विभिन्न स्तरों पर मूल्यांकन किया गया। सत्र की शुरुआत प्रतिभागियों और AHA टीम के बीच परिचय के साथ हुई। डॉ. सुनील कुमार अरोड़ा ने BLS की अवधारणा, इसके आवश्यक घटकों और आपात स्थिति में इंटरफेस के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया, विस्तृत स्पष्टीकरण के बाद, प्रतिभागियों को समूहों में विभाजित करने के लिए कहा गया, और सभी निर्देशों ने प्रत्येक समूह का प्रभार लिया और उन्हें दिखाया कि कैसे करना है सीपीआर करें.

अभ्यास के दौरान प्रतिभागियों की देखरेख और मार्गदर्शन किया गया, जिससे प्रतिभागियों में आत्मविश्वास पैदा हुआ। उन्हें अलग-अलग डमी के वयस्क, बच्चे और शिशु पुनर्जीवन के लिए उचित तकनीकों का अभ्यास करने और सीखने का मौका मिला।

प्रशिक्षण में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

01 श्री अरुण कुमार गुप्ता।
02 श्री ललता प्रशाद शर्मा।
03 श्री ओम प्रकाश शुक्ला।
04 श्री पुरुषोत्तम दास वर्खिया।
05 श्रीमती मोनिका।
06 डॉक्टरअनिता यादव ।
07 श्री शान मोहम्मद।
08 श्री विनोद महेश्वरी।
09 श्री जतिन महेश्वरी।
10 श्रीमती ज्योति गुप्ता।
11 श्रीमती भावना गुप्ता।
12 श्रीमती अन्नू।
13 कुमारी मीरा सेठ।
14 कुमारी तननु।
15 श्री दीपक शर्मा।
16 श्री दमनदीप सिंह ।
17 श्री वीर सिंह चौहान।

उपरोक्त सभी दिल्ली ब्रिगेड के प्रशिक्षित प्रशिक्षक हैं।

दिल्ली सरकार द्वारा मृतक के परिवार को दी जाएगी 10 लाख रुपये की सहायता राशि

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली में कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है और भाजपा शासित केंद्र सरकार जिसके अंतर्गत दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर व सुरक्षा व्यवस्था आती है, वो कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह फेल हो चुकी है। तभी अपराधियों का मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि, पिछले दिनों सुंदर नगरी में लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक 28 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई।

बुधवार को मुख्यमंत्री ने सुंदर नगरी में जाकर मृतक के परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। साथ ही दिल्ली सरकार की ओर से मृतक के परिवार की 10 लाख रुपये की सहायता राशि भी दी जाएगी।

इस मौके पर सीएम आतिशी ने कहा कि, "भाजपा शासित केंद्र सरकार के पास दिल्ली में सिर्फ़ एक काम है - दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को संभालना; लेकिन वो इसमें पूरी तरह से फेल है।दिल्ली में सरेआम गोलियाँ चलना, उगाही, मर्डर रोजमर्रा की बात हो गई है, लेकिन गृहमंत्री अमित शाह चुनावी रैलियों में व्यस्त है।"

उन्होंने कहा कि, ₹गृहमंत्री राजनीति करने के बजाय दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को सम्भालने की अपनी जिम्मेदारी निभाए, उनकी नाकामी से दिल्ली क्राइम कैपिटल बन चुकी है। दिल्ली में गुंडागर्दी करने वालों में कोई भी डर नहीं बचा है; उन्हें लगता है कि, वो खुलेआम अपराध कर सकते और पुलिस कुछ नहीं करेगी। इसलिए आज देश की राजधानी में लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था 1990 के मुंबई अंडरवर्ल्ड जैसी हो गई है, जहां गैंगस्टर्स का राज था।"

सीएम आतिशी ने कहा कि, "सुंदर नगरी में एक युवक की जान इसलिए गई क्योंकि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बदहाल हो गई है। ये बहुत दुखद बात है कि देश की राजधानी में रोज ऐसी घटनाएं हो रही है। कभी राजौरी गार्डन में गोलियाँ चलने की घटना सुनने को मिलती है तो कभी नांगलोई में ड्यूटी पर पुलिस वाले की जान चली जाती है। कभी शोरूम के बाहर गोलियाँ चलती है तो कभी वेलकम इलाक़े में 14 राउंड गोलियां चलने की ख़बर आती है।"

उन्होंने कहा कि, "आज दिल्ली गैंगस्टर कैपिटल हो गया है। दिल्ली में क्राइम करने वालों, मर्डर करने वालों, उगाही करने वालों, गुंडागर्दी करने वालों में कोई भी डर नहीं बचा है। उन्हें लगता है कि, वो खुलेआम अपराध कर सकते और पुलिस कुछ नहीं करेगी।"

सीएम आतिशी ने कहा कि, "आज यहाँ सुंदर नगरी में भी पीड़ितों का परिवार यही कह रहा है कि, असल आरोपी जो इस इलाक़े के गुंडे है, हर तरह के अपराध करते है और इस परिवार के बेटे को मारा है, उसकी गिरफ़्तारी नहीं हुई है। जो दो लोग गिरफ़्तार हुए है, उन्होंने ख़ुद से सरेंडर किया है और पुलिस कोई कारवाई नहीं कर रही है।"

उन्होंने कहा कि, "आज देश की राजधानी में लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था का बुरा हाल हो गया है। एक समय में जिस तरह बॉम्बे में अंडरवर्ल्ड-गैंगस्टर्स का राज था ठीक उसी तरह आज दिल्ली का भी यही हाल हो गया है।"

सीएम ने कहा कि, ₹मैं आज देश के गृहमंत्री अमित शाह से कहना चाहती हूँ कि जब पूरी दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था आपके अंतर्गत आती है, तो वो इस दिशा में कुछ क्यों नहीं कर रहे है? दिल्ली में रोज़ उगाही, मर्डर, गोलियाँ चलना आम बात हो गई है लेकिन देश के गृहमंत्री को चुनाव प्रचार करने के अलावा और कुछ काम नहीं है। गृहमंत्री कभी हरियाणा कभी झारखंड कभी महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे है और दिल्ली में खुलेआम 28 साल के एक युवक की छुरा मारकर हत्या कर दी जाती है।"

उन्होंने कहा कि, ₹भाजपा के पास पूरी दिल्ली में सिर्फ एक काम है, दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को, पुलिस व्यवस्था को ठीक रखना ताकि जनता सुरक्षित रहे लेकिन वो इसमें भी फेल हो गई है।"

सीएम आतिशी ने कहा कि, "आज मैं अमित शाह से पूछना चाहती हूँ कि, वो दिल्लीवालों को कैसे सुरक्षित रखेंगे? वो अपने राजनीतिक काम छोड़े, भाजपा का चुनाव प्रचार-प्रसार छोड़े और दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर और सुरक्षा व्यवस्था को ठीक रखने का अपना काम सुचारू रूप से करें।₹

सीएम आतिशी ने अपने एक्स(ट्विटर) हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा कि, ₹सुंदर नगरी में पिछले दिनों दिनदहाड़े 28 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई। आज मृतक के परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। दिल्ली सरकार की ओर से मृतक के परिवार को 10 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। भाजपा शासित केंद्र सरकार के पास दिल्ली में सिर्फ़ एक काम है - दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को संभालना। लेकिन वो इसमें पूरी तरह से फेल है। शहर में सरेआम गोलियाँ चलना, उगाही, मर्डर रोजमर्रा की बात हो गई है। लेकिन गृहमंत्री अमित शाह चुनावी रैलियों में व्यस्त है। अमित शाह जीः राजनीति करने के बजाय दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को सम्भालने की अपनी जिम्मेदारी निभाए। आपकी नाकामी से दिल्ली क्राइम कैपिटल बन चुकी है।

चिंताजनक: दिल्ली-NCR के 75 प्रतिशत परिवार का एक सदस्य बीमार, सर्वे में प्रदूषण से गैस चैंबर बने इलाकों का पता चला हाल

परिवहन विशेष

एक सर्वेक्षण से पता चला है कि NCR में वायु प्रदूषण के कारण 75% परिवार प्रभावित हैं। दिल्ली गुरुग्राम नोएडा फरीदाबाद और गाजियाबाद के 21000 से अधिक निवासियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि कम से कम एक सदस्य गले में खराश या खांसी से पीड़ित है। बढ़ते प्रदूषण के कारण 58% परिवारों ने सिरदर्द की शिकायत की जबकि 50% ने सांस लेने में कठिनाई या अस्थमा की समस्या बताई।

नई दिल्ली। गैस चेंबर बने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक सर्वेक्षण से पता चला है कि एनसीआर में 75 प्रतिशत परिवारों में से कम से कम एक सदस्य गले में खराश या खांसी से पीड़ित है। सर्वेक्षण में दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद के 21,000 से अधिक निवासियों से प्रतिक्रियाए ली गई।

इसमें 63 प्रतिशत उत्तरदाता पुरुष थे और 37 प्रतिशत महिलाएं थीं। ऑनलाइन कम्युनिटी प्लेटफॉर्म लोकल सर्किल्स ने दावा किया है कि सर्वे शामिल एनसीआर के 58 प्रतिशत परिवारों ने बढ़ते प्रदूषण के स्तर के कारण सिरदर्द का अनुभव किया, जबकि 50 प्रतिशत ने कहा कि परिवार का कोई सदस्य सांस लेने में कठिनाई या अस्थमा से जूझ रहा है।

प्रदूषण से लड़ने को क्या कदम उठा रहे परिवार

यह पूछे जाने पर कि क्षेत्र में वायु गुणवत्ता स्तर 400 पर पहुंचने पर वे क्या कदम उठा रहे हैं, 27 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि वे प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर का उपयोग कर रहे हैं, जबकि 23 प्रतिशत ने कहा कि वे खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं।

खाने-पीने पर दे रहे ज्यादा ध्यान

बाकी ने संकेत दिया कि वे केवल प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों का सेवन बढ़ाकर इससे निपट रहे हैं। सर्वेक्षण से यह भी पता चला कि कम से कम एक बीमार सदस्य वाले परिवारों का प्रतिशत 1 नवंबर को 69 प्रतिशत से बढ़कर 19 नवंबर तक 75 प्रतिशत हो गया

एयर प्यूरीफायर की बढ़ी मांग

इस बीच, एयर प्यूरीफायर का उपयोग काफी बढ़ गया है, 19 अक्टूबर को इनका उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत 18 प्रतिशत से बढ़कर एक महीने बाद 27 प्रतिशत हो गया।

गुरुग्राम से दिल्ली की कनेक्टिविटी कैसे होगी बेहतर? लाखों वाहन चालकों को राहत के लिए बन रहा प्लान

परिवहन विशेष न्यूज

थ्री लेयर एलिवेटेड हाईवे विकसित कर पांच किलोमीटर के अंतराल पर इंटरचेंज यानी जंक्शन की सुविधा पर जोर देना होगा। सभी जंक्शन क्लोवरलीफ की तरह बनाने होंगे ताकि किसी भी तरफ से आने वाले वाहन पूरी स्पीड के साथ आगे दूसरी तरफ निकल जाएं। इससे कहीं भी ट्रैफिक का दबाव नहीं दिखाई देगा। कई शहरों में भी थ्री लेयर एलिवेटेड रोड बनाने के ऊपर जोर दिया जा रहा है।

गुरुग्राम। गुरुग्राम। ग्रेप चरण चार लागू होने के बाद टाउन एंड कंट्री प्लॉनिंग विभाग की तरफ से मंगलवार को शहर की लाइसेंस कॉलोनियों तथा लाइसेंस प्रोजेक्ट के चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर सख्ती बरतनी शुरू की गई। इसी कड़ी में जिला नगर योजनाकार एन्फोर्समेंट (डीटीपीई) मनीष यादव की तरफ से टीमों का गठन कर सर्वे शुरू करा दिया गया है।

इसमें सहायक नगर योजनाकार, जूनियर इंजीनियरों ने साइटों का निरीक्षण किया और मौके पर चलते पाए गए निर्माण कार्यो की फोटोग्राफी कर सूची तैयार कर इनके मालिकों के विरुद्ध एनजीटी नियमों के तहत लगभग 25-25 हजार रुपये के चार अलग- अलग चालान काटे गए। ये निर्माण डीएलएफ, सुशांत लोक रिहायशी कॉलोनियों में किए जा रहे थे जबकि अभी निर्माण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है।

10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन जब्त

उधर, प्रदूषण नियंत्रण को लेकर गुरुग्राम यातायात पुलिस भी वाहन चालकों पर निरंतर कार्रवाई कर रही है। सड़कों पर चल रहे दस साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को जब्त किया जा रहा है। बीते चार दिनों में 19 वाहनों को जब्त किया गया है। वहीं ग्रेप तीन लागू होने के बाद से अब तक 25 सौ वाहनों का चालान किया गया है।

गुरुग्राम के लोगों के लिए एडवाइजरी जारी

प्रदषण को लेकर ग्रेप के चरण लागू होने के बाद यातायात पुलिस ने भी गुरुग्राम के लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की थी, लेकिन इसके बाद भी बड़ी संख्या में वाहन चालक सड़कों पर अपने वाहन लेकर निकल रहे हैं। यातायात पुलिस की तरफ से बताया गया कि प्रदूषण फैलाने वाले 484 वाहनों के खिलाफ चालान किया गया।

वहीं सड़क पर 19 दस साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन चलते पाए गए। इन्हें टीम ने जब्त कर लिया। डीसीपी ट्रैफिक वीरेंद्र विज ने कहा कि आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई से बचने के लिए सभी लोग यातायात नियमों को पालन करें।

अब तक हुई कार्रवाई

15 से 18 नवंबर तक कार्रवाई प्रदूषण में----484

पुराने वाहन----19

बीएस तीन पेट्रोल--532

बीएस चार डीजल---1467

कुल 2537

अवैध व्यावसायिक गतिविधि करने पर तीन इमारत सील

टाउन एंड कंट्री प्लॉनिंग विभाग के जिला नगर योजनाकार एन्फोर्समेंट (डीटीपीई) की तरफ से मंगलवार को डीएलएफ फेज तीन में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर सीलिंग अभियान चलाया गया।

इस दौरान डीएलएफ फेज तीन स्थित नाथूपुर रोड, एस-ब्लाक तथा वी-ब्लाक में तीन मकानों में सीलिंग की कार्रवाई हुई। इनमें अवैध व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर विभाग के पास सीएम विंडो के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई थी।

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एन्फोर्समेंट टीम सबसे पहले नाथूपुर रोड पहुंची जहां बेसमेंट, स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार फ्लोर में अवैध व्यावसायिक गतिविधि के रूप में जिम और गेस्ट हाउस चलाया जा रहा था।

इसमें टीम ने बेसमेंट और स्टिल्ट पार्किंग को सील कर दिया। इसके बाद टीम एस-ब्लॉक और वी-ब्लॉक पहुंची। यहां पर दोनों इमारतों में हर फ्लोर पर चार-चार स्वतंत्र यूनिट बनाकर अवैध तरीके से व्यावसायिक गतिविधि के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसके चलते दोनों इमारतों को सील कर दिया गया।

इमारत मालिकों के विरुद्ध दर्ज होगी FIR

हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट एक्ट 1975 के तहत रिहायशी मकान में अवैध व्यावसायिक गतिविधि नियमों के विरुद्ध है। अब विभाग की तरफ से इन इमारत मालिकों के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। यह कार्रवाई डीटीपीई मनीष यादव के नेतृत्व में की गई। इस दौरान एटीपी अनीश ग्रोवर बतौर डयूटी मजिस्ट्रेट, जूनियर इंजीनियर हर्षित सलूजा, बबीता तथा विभाग का अन्य स्टाफ मौजूद रहा।

देश की सबसे स्मार्ट टाउनशिप में घर का सपना होगा पूरा, यहां जानें जमीन के रेट; दिल्ली के पास है ये लोकेशन

दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोरके अंतर्गत देश की सबसे स्मार्ट टाउनशिप में से एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप में रहने का सपना अब जल्द पूरा हो सकेगा। आईआईटीजीएनएल की ग्रुप हाउसिंग भूखंड योजना जल्द लॉन्च होगी। 4 ग्रुप हाउसिंग भूखंडों की स्कीम में फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) 5 .5 होगा। 2024-25 की भू आवंटन की दरें तय जल्द होगी स्कीम लॉन्च।

ग्रेटर नोएडा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी, DMIC) के अंतर्गत देश की सबसे स्मार्ट टाउनशिप में से एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप में रहने का सपना अब जल्द पूरा हो सकेगा। आईआईटीजीएनएल की ग्रुप हाउसिंग भूखंड योजना जल्द लांच होगी।

ग्रुप हाउसिंग के चार भूखंडों की स्कीम में फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) 5.5 होगा। आईआईटीजीएनएल (IITGNL) की बोर्ड बैठक में 2024-25 की भू आवंटन की दरें तय हो चुकी हैं। अब स्कीम लॉन्च करने के निर्देश दिए गए हैं।

जमीन के रेट पर लगी मुहर

दरअसल, आईआईटीजीएनएल की तरफ से बिल्डर भूखंडों की स्कीम लॉन्च करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन ई-ऑक्शन के लिए आरक्षित मूल्य न होने के कारण रुकी हुई थी। आईटीजीएनएल की बोर्ड बैठक में रेट पर मुहर लग गई। टाउनशिप में 44,400 रुपये प्रति वर्ग मीटर आरक्षित मूल्य तय किया गया है।

भूखंड का एरिया है कितना?

देश की सबसे स्मार्ट टाउनशिप होने के चलते एनसीआर व देश के कई बड़े बिल्डर ग्रुप हाउसिंग ने निवेश करने की इच्छा जताई है।

आईआईटीजीएनएल की निदेशक प्रेरणा सिंह ने बताया कि चार ग्रुप हाउसिंग भूखंडों में से एक भूखंड 34500 वर्ग मीटर, दूसरा भूखंड 54400, तीसरा भूखंड 70000 और चौथा भूखंड 94000 वर्ग मीटर क्षेत्र का है।

चारों भूखंड की कीमत 1123 करोड़

आरक्षित मूल्य के आधार पर इन चारों भूखंडों की कुल कीमत लगभग 1123 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इन भूखंडों का आवंटन ऑनलाइन नीलामी के जरिए होगा। इसके साथ ही आईआईटीजीएनएल बोर्ड ने 2024-25 के लिए उद्योगों, वाणिज्यक संपत्तियों की दरें भी तय कर दी हैं।

इंडस्टी और कमर्शियल जमीन के रेट अलग

औद्योगिक भूखंडों की दर 23,900 रुपये प्रति वर्ग मीटर और वाणिज्यक भूखंडों की दर 75,400 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी। बैठक में आईआईटीजीएनएल के प्रबंध निदेशक एनजी रवि कुमार, निदेशक प्रेरणा सिंह, श्रीलक्ष्मी वीएस, एनआईसीडीसी के प्रबंध निदेशक रजत कुमार सैनी, कंपनी सेक्रेटरी पतंजलि दीक्षित आदि मौजूद रहे।

शहीद शुभम को समर्पित होगी गायक अनूप जलोटा की भजन संध्या

संजय साग़र सिंह

आगरा, अमर शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता की प्रथम पुण्य स्मृति में एक अनूठे आयोजन का कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसमें देशभक्ति और ईश भक्ति का संगम देखने को मिलेगा। यह भजन संध्या 'एक शाम बलिदान के नाम' के रूप में 22 नवंबर को शाम 6.30 बजे से सूरसदन प्रेक्षागृह, आगरा में आयोजित की जाएगी। इस मौके पर प्रसिद्ध भजन गायक अनूप जलोटा अपने सुरों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करेंगे।

कैप्टन शुभम गुप्ता, जो पिछले वर्ष 22 नवंबर को राजौरी में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए थे, उनकी शहादत को याद करते हुए यह भजन संध्या आयोजित की जा रही है। इस अवसर पर देशभक्ति के नारों के साथ-साथ भक्ति के गीतों का भी समागम होगा, जिसमें 'जयहिंद', 'वंदेमातरम', 'जय श्रीराम' और 'राधे-राधे' की गूंज सुनाई देगी।

अनूप जलोटा, जिन्हें 'भजन सम्राट' की उपाधि प्राप्त है और जो 2012 में पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं, इस आयोजन का प्रमुख आकर्षण होंगे। उनकी आवाज़ ने दुनिया भर में लाखों श्रोताओं का दिल जीता है। इसके अलावा, कार्यक्रम में भारत विकास परिषद, आगरा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा व्यवस्था की जा रही है।

यह आयोजन सभी के लिए खुला रहेगा, और प्रवेश के लिए कोई भी टिकट जारी नहीं किए गए हैं। श्रोता पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर सीट ग्रहण कर सकेंगे।

इस आयोजन को सफल बनाने के लिए विभिन्न प्रमुख व्यक्ति और समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनमें क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ तरुण शर्मा, राष्ट्रीय प्रकल्प चेयरमैन डॉ केशव दत्त गुप्ता, राष्ट्रीय प्रकल्प सदस्य एड. बसंत गुप्ता, क्षेत्रीय सचिव प्रमोद सिंघल क्षेत्रीय दायित्वधारी सोमदेव सारस्वत, प्रांतीय संरक्षक विनय सिंघल व डॉ कैलाश सारस्वत, मुख्य मार्गदर्शक वीरेंद्र सिंघल, मार्गदर्शक रवि शिवहरे, प्रांतीय अध्यक्ष उमेश बंसल, उपाध्यक्ष टीटू गोयल, अजय शिवहरे, प्रांतीय विस्तार प्रमुख धर्मगोपाल मित्तल, प्रकल्प प्रभारी चंद्रवीर फौजदार, प्रशांत अग्रवाल, तपन अग्रवाल, पुष्पेंद्र सिसोदिया, मनीष जैन, गुंजन अग्रवाल, सह समन्वयक राजेश गोयल, शाखा अध्यक्ष मनोज अग्रवाल पोली भाई, कुलभूषण गुप्ता, कमलेश गुप्ता, अशोक गुप्ता, दिलीप गुप्ता, राजीव गुप्ता एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल थे।

गुरुग्राम में बिजवासन के पास मालगाड़ी के दो पहिए ट्रैक से उतरे, दो घंटे तक रेल यातायात प्रभावित

परिवहन विशेष न्यूज

गुरुग्राम में बिजवासन रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के दो डिब्बे पटरी से उतरने से दिल्ली-गुड़गांव रेलवे ट्रैक पर करीब दो घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। इस घटना से छह से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुईं और यात्री परेशान रहे। ट्रैक को क्रेन की मदद से क्लियर कराया गया और फिर ट्रेनों को आगे के लिए रवाना किया गया। रेलवे अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है।

गुरुग्राम। दिल्ली से गुड़गांव की ओर आ रही मालगाड़ी के दो डिब्बे बिजवासन रेलवे स्टेशन से आगे ट्रैक से उतर गए। इससे गुड़गांव दिल्ली रेलवे ट्रैक पर रेल यातायात प्रभावित हो गया। इस घटना से छह से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित रहीं और यात्री गुड़गांव, गढ़ी हरसरू, रेवाड़ी समेत अन्य स्टेशनों पर परेशान होते रहे।

बताया जाता है एक मालगाड़ी बुधवार रात आठ बजे दिल्ली से गुड़गांव रेलवे स्टेशन की तरफ आ रही थी। बिजवासन से आगे ट्रेन के दो डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए। लोको पायलट ने फौरन रेल अधिकारियों को सूचना दी।

इस ट्रैक की ट्रेनों को स्टेशनों पर रोका

इसके बाद ट्रैक से गुजर रही कई ट्रेनों को आसपास के स्टेशन पर रोक दिया गया। क्रेन लगाकर पहले मालगाड़ी से उन दो डिब्बों का सामान उतारा गया और फिर ट्रेन को ट्रैक पर चढ़कर उसे आगे के लिए रवाना किया गया।

दो घंटे में क्लियर हुआ ट्रैक

करीब दो घंटे बाद ट्रैक को क्लियर कर ट्रेनों को आगे रवाना किया जा सका। इस घटना से यात्रियों को काफी परेशानी हुई। ट्रैक बाधित होने से स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस और दिल्ली रेवाड़ी पैसेंजर ट्रेन डेढ़ से दो घंटे की देरी से गुड़गांव रेलवे स्टेशन पर पहुंची।

रेल अधिकारियों ने बताया कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि रेलवे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है।

अनुरक्षण कार्य के कारण रेल यातायात प्रभावित

वहीं, अनाजमंडी-रेवाड़ी स्टेशनों के मध्य फाटक संख्या 61 पर गर्डर लॉन्चिंग कार्य के कारण ट्रैफिक ब्लाक लिया जा रहा है। ब्लाक के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। इसमें गुड़गांव स्टेशन से गुजरने वाली भी कई ट्रेनें शामिल हैं।

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार कार्य के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे पर संचालित कई ट्रेनें प्रभावित होंगी। ट्रेन संख्या 14312 भुज-बरेली एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी होकर संचालित होगी। परिवर्तित मार्ग में यह ट्रेन रींगस, श्रीमाधोपुर, नीमकाथाना व नारनौल स्टेशनों पर ठहरेगी।

बाकी ट्रेनों की लिस्ट

19601 उदयपुर सिटी-न्यूजलपाईगुडी एक्सप्रेस उदयपुर सिटी से प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन अलवर-करनावास न्यू स्टेशन के मध्य एक घंटे 20 मिनट रेगुलेट रहेगी। ट्रेन संख्या 19407 साबरमती-वाराणसी एक्सप्रेस भी अलवर-करनावास न्यू स्टेशन के माध्य एक घंटे 20 मिनट रेगुलेट रहेगी। ट्रेन संख्या 14662 जम्मूतवी-बाड़मेर शालीमार एक्सप्रेस रेवाड़ी स्टेशन पर 25 मिनट रेगुलेट रहेगी। वहीं परिवर्तित मार्ग पर चल रही जैसलमेर काठगोदाम रानीखेत एक्सप्रेस अब अपने समय से निर्धारित स्टेशनों से रवाना होगी।

गंगा का मैल सख्ती व जवाबदेही से ही दूर होगा

सुरेश हिंदुस्तानी

अमेरिका के इस चुनाव में भारत के लोकसभा चुनाव की तरह ही प्रचार किया गया। कई प्रकार के नैरेटिव स्थापित करने का प्रयास किए गए। वामपंथी विचार के मीडिया ने ट्रम्प की राह में अवरोध पैदा करने के भरसक प्रयास किए।

अमेरिका में रिपब्लिकल पार्टी की ऐतिहासिक विजय के बाद अब यह तय हो गया है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। अमेरिका का इतिहास बताता है कि ट्रम्प की यह जीत उनकी ऐतिहासिक वापसी है। अमेरिका में यह विजय किसी चमत्कार से कम नहीं है। 130 वर्ष के अमेरिकी इतिहास में यह पहली बार है, ज़ब किसी ने यह कारनामा किया है। डोनाल्ड ट्रम्प ने लगातार तीसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, जिसमें पहली और तीसरी बार वे सफल रहे, दूसरी बार के चुनाव में जो बाइडेन से पराजित हो गए। इस चुनाव में पराजित होने के बाद ट्रम्प अमेरिका में राजनीतिक तौर पर लगातार सक्रिय रहे। उनका मिशन फिर से राष्ट्रपति बनना ही था, जिसे उन्होंने बखूबी अंजाम देकर एक नया कीर्तिमान बना दिया। चुनाव में उनकी प्रतिद्वंदी कमला हैरिस यकीनन राजनीतिक समझ रखती थी, लेकिन यह समझ किसी भी प्रकार से सफलता की परिचायक नहीं बन सकी। हालांकि अमेरिकी मीडिया के एक वर्ग ने तो उनको भावी राष्ट्रपति के रूप में प्रचारित कर दिया। लेकिन यह नैरेटिव भी उनके लिए जीत का मार्ग नहीं बना सका। यहां एक ख़ास तथ्य यह भी माना जा सकता है कि कमला हैरिस को भारतीय मूल का बताने का सुनियोजित प्रयास किया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि भारतीय मूल के मतदाताओं को उनके पक्ष में लाया जा सके, लेकिन वे जिन हाथों में खेल रही थी, वह लाइन

भारत के लिए राजनीतिक तौर सही नहीं थी।

वैश्विक राजनीति के जानकार डोनाल्ड ट्रम्प की जीत कई निहितार्थ निकाल रहे हैं। कई विश्लेषक ट्रम्प की जीत को भारत की कूटनीतिक सफलता के तौर पर भी स्वीकार कर रहे हैं। इसका एक कारण यह माना जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर भारत सरकार जिस नीति और विचार को लेकर कार्य कर रही है, उसकी झलक ट्रम्प के विचारों में भी दिखाई देती है। इसके अलावा ट्रम्प का कहना है कि अमेरिका की खोई ताकत को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। आज अमेरिका कहने मात्र को ही महाशक्ति है, लेकिन उसका वैसा दबदबा आज नहीं है, जो पहले हुआ करता था। इस बीच भारत ने महाशक्ति बनने की दिशा में तीव्र गति से अपने कदम बढ़ाए हैं, इसलिए आज विश्व के अनेक देश भारत को महाशक्ति के रूप में देखने लगे हैं। हमें स्मरण होगा कि रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध के दौरान भारत के नागरिक पूरे सम्मान के साथ भारत लौटे थे। उस समय भारत के नागरिकों के समक्ष यूक्रेन की सेना ने अपने हथियार नीचे कर लिए थे। यह केवल एक दृश्य नहीं, बल्कि भारत की शक्ति का ही परिचायक था। भारत की इस बढ़ती शक्ति से अमेरिका भी भली भांति परिचित है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बारे में कई बार यह कहा जा चुका है कि भारत चाहे तो युद्ध रुकवा सकता है। इसका तात्पर्य यही है कि आज का भारत विश्व के लिए एक ताकत बन चुका है।

अमेरिका के इस चुनाव में भारत के लोकसभा चुनाव की तरह ही प्रचार किया गया। कई प्रकार के नैरेटिव स्थापित करने का प्रयास किए गए। वामपंथी विचार के मीडिया ने ट्रम्प की राह में अवरोध पैदा करने के भरसक प्रयास किए। यहां तक कि उनको सनकी और विलेन कहने में भी गुरेज नहीं किया गया। यही तो भारत में किया गया। वामपंथी समूह ने भारत के लोकसभा चुनावों में सरकार के विरोध में जहरीली भाषा का प्रयोग किया। फिर भी आख़रिकार नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो गए। अब ऐसा लगने लगा है कि मतदाता बहुत समझदार हो गया है। उसको किसी भी प्रकार से भ्रमित नहीं किया जा सकता। उसे अब देश दुनिया की समझ हो गई है, इसलिए वह वर्तमान के साथ कदम मिलाकर चलने की ओर अग्रसर हुआ है।

विश्व के कई देश आज कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। कोरोना के बाद कई देशों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, उसे पटरी पर लाने के लिए उस देश की सरकार की ओर से भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। इन समस्याओं में कई समस्याएं ऐसी हैं, जो सबके सामने हैं। आतंकवाद एक विकराल समस्या बनता जा रहा है। अमेरिका भी इससे ग्रसित है। रूस और यूक्रेन की बीच तनातनी कम नहीं हो रही। इजराइल और हमास के बीच युद्ध जैसे हालात हैं। अमेरिका में ट्रम्प के पुनः राष्ट्रपति बनने के बाद यह लग रहा है कि अब आतंक के सहारे भय का वातावरण बनाने वाले किसी भी कदम को पूरे जोश के साथ रोकने का प्रयास किया जाएगा।

अमेरिका में ट्रम्प की जीत से भारत के पड़ोसी देश यानि पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश में सुगबुगाहट प्रारम्भ हो गई है, क्योंकि यह देश भारत को हमेशा अस्थिर करने की फिराक में रहते हैं। हम वह वाकिया अभी तक भूले नहीं हैं, ज़ब अमेरिका ने आतंक के विरोध में बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए ओसामा बिन लादेन को मौत के घाट उतार दिया था, हालांकि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा थे, लेकिन आतंक के विरोध में ट्रम्प का भी वैसा ही रवैया माना जा सकता है। इसी प्रकार चीन के समक्ष भी स्थिति पैदा होती दिखाई दे रही है। हम जानते हैं कि अमेरिका हमेशा से ही पाकिस्तान से आतंक के विरोध में कार्यवाही करने के लिए कहता है, लेकिन जो देश आतंक के आकाओं के सहारे ही चल रहा हो, वह आतंक के विरोध में कैसे कार्यवाही कर सकता है। अब अमेरिका में ट्रम्प के पुनः आने के बाद इस बात की संभावना बढ़ गई है कि अब पाकिस्तान दिखावे के लिए ही सही, लेकिन आतंक के आकाओं के खिलाफ एक्शन लेगा।

लोक उत्सव से तंत्र का यंत्र बन गए हैं चुनाव

इस साल चुनाव देखते-दिखाते, सुनते-बतियाते तथा लड़ते-लड़ाते हुए मुझे 40 बरस पूरे हो जाएंगे। मुझे याद है 1984-85 का वह अभूतपूर्व चुनाव, जिसमें राजीव गांधी की चुनावी आंधी ने सब भविष्यवाणियों को झुठला दिया था। उस चुनाव में प्रणय रॉय द्वारा इंडिया टुडे पत्रिका में किए विश्लेषण को पढ़कर मेरी चुनावी विश्लेषण और भविष्यवाणी में दिलचस्पी जगी थी।

पिछले चार दशकों में चुनावों के दौरान देश और दुनिया के अलग-अलग कोनों की धूल फांकने का मौका मिला, अखबार, टी.वी. और अब यूट्यूब पर विश्लेषण किया है, एक बार खुद चुनाव लडने और कई बार चुनाव लड़ाने का अवसर भी मिला है। जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है चुनाव का शाब्दिक और कानूनी चेहरा भले ही वही रहा है, लेकिन चुनाव नामक इस घटना का स्वरूप बुनियादी रूप से बदल गया है। मुझे याद है 1994 में जब मुझे जर्मनी के चुनाव देखने का मौका मिला, तब आंखों में चुभा था कि वहां सड़कों पर, बाजार में, होटल में और यहां तक कि अखबार के पन्नों पर भी कहीं चुनाव का कोई माहौल ही नहीं था। उन दिनों तक भारत के चुनाव एक मेले जैसे हुआ करते थे। दीवार लेखन, पोस्टर, बैनर, झंडियों की लडियां या फिर बड़े-बड़े झंडे। इनसे पूरा शहर पटा रहता था, चुनाव चल रहे हैं इसका आंख खोलने भर से पता रहता था।

पब्लिक को कुछ तकलीफ जरूर होती थी, जैसी हर त्यौहार में होती है। लेकिन कुल मिलाकर यह लोकोत्सव होता था, जिसमें रौनक थी, जनता के जनार्दन होने की खनक थी। अब चुनाव आयोग की तरफ से ही नाना प्रकार की बंदिशें लग गई हैं, सड़क से पोस्टर, बैनर, झंडियां लगभग गायब हो चुकी हैं। कभी अखबार में बड़ा विज्ञापन दिख जाता है, बस। चुनाव प्रचार घर की चारदीवारी के भीतर सिमट गए हैं, अक्सर केवल ड्राइंग रूम तक।

मेरे बचपन में ही चुनावी बुखार का पैमाना चुनावी रैलियां हुआ करती थीं। नेता आपकी पसंद की पार्टी का हो या नहीं, सारा शहर उसके भाषण को सुनने और उसकी रैली देखने जाया करता था। रैली में जुटी भीड़ और जनता की प्रतिक्रिया से ही चुनावी हवा का अनुमान लगाया जाता था। इस मायने में भी भारत का चुनाव यूरोप और अमरीका से बहुत अलग था, जहां नेता जनसंपर्क सिर्फ टी.वी. कैमरे के लिए करते थे। धीरे-धीरे हम भी उसी राह पर चल निकले हैं। चुनाव रैलियों से हटकर अब टी.वी. के पर्दे पर खिसक आया है। रैलियां अब भी होती हैं, लेकिन टी.वी. के लिए। अब चुनावी रैली में सामान्य मतदाता ईने-गिने ही होते हैं, चुनावी रैली अपने समर्थकों के शक्ति प्रदर्शन का बहाना होती है। रैली में भी नेता जनता से बहुत दूर होते हैं।

सड़क और मैदान से ही खिसक चुनावी प्रचार आंगन और ड्राइंग रूम में चले आने से चुनाव की भाषा ज्यादा नफीस होनी चाहिए थी, खर्च घटना चाहिए था, लेकिन इसका ठीक उलटा हो रहा है। पहले गाली-गलौच, अनर्गल आरोप और भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल विपक्षी दलों में भी बिल्कुल हाशिए पर खड़े नेता किया करते थे। पिछले 10 वर्षों में संवैधानिक पदों पर विराजमान नेताओं ने भी इस भाषा की मर्यादा को तोडने में अग्रणी भूमिका अख्तियार कर ली है। हर चुनाव में ही खर्चा दिन दोगुना, रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। पहले कभी-कभार ऐसा राजनीतिक कार्यकत्ता मिल जाता था, जो नाम मात्र के पैसे खर्च कर चुनाव जीत जाता था। अब ऐसे अपवाद ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। विधानसभा चुनाव में चुनावी खर्च की सीमा भले ही 40 लाख रुपए हो, लेकिन हर गंभीर उम्मीदवार औसतन 5-10 करोड़ रुपए खर्च करने पर मजबूर है। सम्पन्न राज्यों में यह राशि 25-30 करोड़ रुपए है तो कुछ शहरी सीटों पर 50 करोड़ रुपए या उससे भी अधिक है। जरूरी नहीं कि लोग पैसा लेकर उसी उम्मीदवार को वोट डालेंगे लेकिन अब देश के अधिकांश इलाकों में वोटर भी चुनावी दक्षिणा को अपना अधिकार मानता है।

- :सौजन्य :-
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV
Drive the Future

क्वांटम एनर्जी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वित्तीय सेवाओं हेतु आई-लोन के साथ किया सहयोग

परिवहन विशेष न्यूज

क्वांटम एनर्जी ने लोनटैप ग्रुप के तहत ग्रीन-फोकस्ड फाइनेंस कंपनी आई-लोन के साथ साझेदारी की है, ताकि भारत भर में अपने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ग्राहकों के लिए लचीले फाइनेंसिंग विकल्प उपलब्ध कराए जा सकें। इस सहयोग का उद्देश्य प्लाज्मा, मिलान और बिज़नेस स्कूटर सहित क्वांटम एनर्जी के ईवी मॉडल की सामर्थ्य को बढ़ाना है, जो दैनिक यात्रा और व्यावसायिक रसद जैसी विविध आवागमन आवश्यकताओं को पूरा करता है।

साझेदारी लचीले पुनर्भुगतान विकल्पों के साथ वित्तपोषण समाधान पेश करती है, जिससे अग्रिम भुगतान का बोझ कम होता है। ग्राहक 24-36 घंटों के भीतर त्वरित ऋण वितरण, न्यूनतम कागजी कार्रवाई और छिपे हुए या फौजदारी शुल्क की अनुपस्थिति का लाभ उठा सकते हैं। इन सुविधाओं का उद्देश्य खरीदारी प्रक्रिया को सरल बनाना है जबकि यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहक डेटा सुरक्षित रहे।

क्वांटम एनर्जी की प्रबंध निदेशक चक्रवर्ती सी. ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह साझेदारी उनके इलेक्ट्रिक स्कूटर को अधिक सुलभ बनाने और ग्रीन मोबिलिटी में बदलाव का समर्थन करने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि आई-लोन द्वारा प्रदान किए जाने वाले वित्तपोषण विकल्प ग्राहकों को लचीलापन प्रदान करने और क्वांटम एनर्जी की बाजार उपस्थिति का विस्तार करने के लिए

डिज़ाइन किए गए हैं।

आई-लोन (लोनटैप ग्रुप) के सीईओ राजीव दास ने टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने के अपने साझा लक्ष्य पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वित्तपोषण समाधानों में त्वरित अनुमोदन, सुव्यवस्थित प्रक्रियाएँ और अनुकूलनीय पुनर्भुगतान शर्तें शामिल हैं, ताकि भारतीय ग्राहकों के लिए ईवी स्वामित्व को अधिक सुविधाजनक और किफ़ायती बनाया जा सके।

आई-लोन क्वांटम एनर्जी डीलरशिप को वित्तपोषण विकल्पों को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए संसाधनों से भी लैस करेगा। डीलरों के पास त्वरित ऋण प्रसंस्करण के लिए क्यूआर कोड तक पहुंच होगी और आई-लोन की फील्ड टीमों से जमीनी स्तर पर सहायता मिलेगी। इस एकीकरण का उद्देश्य ग्राहकों के लिए समग्र बिक्री और सेवा अनुभव को बढ़ाना है।

2022 में स्थापित कुसलवा इंटरनेशनल की सहायक कंपनी क्वांटम एनर्जी अपनी मूल कंपनी की पांच दशकों की इंजीनियरिंग विशेषज्ञता का लाभ उठाती है। आज तक 10,000 से अधिक इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री के साथ, क्वांटम एनर्जी पहुंच, गुणवत्ता और टिकाऊ गतिशीलता समाधानों पर ध्यान केंद्रित करके ईवी बाजार में अपनी उपस्थिति का विस्तार करना जारी रखती है।

पहाड़ों पर चढ़ेंगे इलेक्ट्रिक वाहन, प्रदूषण कम करने के लिए बड़ा फैसला, अब कुमाऊं पर फोकस

परिवहन विशेष न्यूज

उत्तराखंड चार धाम मार्ग के बाद अब परिवहन विभाग राज्य के अन्य पर्यटक स्थलों के मार्गों पर भी चार्जिंग स्टेशन लगाने जा रहा है। गंगोत्री धाम को छोड़कर अन्य तीन धामों की ओर जाने वाले मार्गों पर करीब 28 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए जा चुके हैं। ऐसे में अब राज्य के सभी पर्यटक स्थलों खासकर कुमाऊं क्षेत्रों के मार्गों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए जाने हैं। इसके लिए 41 बिंदु भी चिह्नित किए गए हैं। परिवहन विभाग का उद्देश्य न सिर्फ राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देना है, बल्कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को भी इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिए पर्यटक स्थलों पर बेरोकटोक आने-जाने के लिए सक्षम बनाना है।

देश की राजधानी दिल्ली समेत तमाम राज्य इन दिनों वायु प्रदूषण से जूझ रहे हैं। उत्तराखंड राज्य भी इससे अछूता नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि उत्तराखंड राज्य का करीब 70 फीसदी हिस्सा जंगल से घिरा हुआ है। पिछले एक सप्ताह के दौरान उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो गई थी। इतना ही नहीं, वनाग्नि और चारधाम यात्रा के दौरान राज्य के मैदानी जिलों में ही नहीं, बल्कि पहाड़ी जिलों में भी वायु गुणवत्ता काफी प्रभावित होती है। इससे न केवल लोगों को परेशानी होती है, बल्कि वायु प्रदूषण अधिक होने से ग्लेशियर पर पीएम 2.5 और पीएम 10 कण जमा हो जाते हैं। इससे ग्लेशियर पिघलने की गति बढ़ जाती है।

इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन किसी चुनौती से कम नहीं: देश और दुनिया में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को देखते हुए भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया है। ताकि देश में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सके। भारत सरकार ने साल 2070 तक देश में कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य रखा है। इसी के चलते भारत सरकार और राज्य सरकारें लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल से जुड़ी एक बड़ी चुनौती इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन हैं। इसलिए उत्तराखंड सरकार पूरे राज्य में ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने पर जोर दे रही है।

पर्वतीय मार्गों पर चार्जिंग स्टेशन से बढ़ेगा पर्यटन: उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। जिसके चलते उत्तराखंड में पर्यटकों की संख्या में भी साल दर साल बढ़ोतरी हो रही है। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाने के लिए दुनिया और दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटक डीजल या पेट्रोल से चलने वाले वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि राज्य में खासकर पहाड़ी इलाकों में ईवी चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में उत्तराखंड परिवहन विभाग अब राज्य के चारधाम यात्रा मार्गों (गंगोत्री मार्ग को छोड़कर) के साथ ही सभी पर्यटक स्थलों के मार्गों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाने पर जोर दे रहा है। ताकि दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटक भी पहाड़ी इलाकों में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल कर सकें।

इन रूटों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन: उत्तराखंड परिवहन निगम ने बदरीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री धाम यात्रा रूट पर कुल 28 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए हैं यानी चारधाम यात्रा रूटों पर परिवहन निगम ने पहले चरण में पांच रूट चिह्नित कर 28 स्थानों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का कॉरिडोर बनाया है। इसके तहत मंगलौर-हरिद्वार-ऋषिकेश रूट पर 7 ईवी चार्जिंग स्टेशन, बड़कोट-यमुनोत्री रूट पर 4 ईवी चार्जिंग स्टेशन, ऋषिकेश-बद्रीनाथ रूट पर 12 ईवी चार्जिंग स्टेशन, रुद्रप्रयाग-केदारनाथ रूट पर 4 ईवी चार्जिंग स्टेशन और उत्तरकाशी-घनसाली रूट पर एक ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए गए हैं। ज्यादातर चार्जिंग स्टेशन गढ़वाल विकास निगम लिमिटेड के गेस्ट हाउस में लगाए गए हैं।

दूसरे चरण में 41 स्थानों पर लगेंगे स्टेशन: ऐसे में अब परिवहन विभाग दूसरे चरण के तहत प्रदेश के 8 जिलों में 41 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने जा रहा है। परिवहन विभाग ने न सिर्फ ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने से संबंधित डीपीआर तैयार कर ली है बल्कि ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए जमीन का चयन भी कर लिया गया है। ऐसे में अब जबकि चारधाम यात्रा समाप्त हो चुकी है, तो जल्द ही प्रदेश के आठ जिलों में 41 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी। परिवहन निगम ने प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटक स्थलों की ओर जाने वाले मार्गों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाने पर जोर दिया है ताकि दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले पर्यटक भी बेहिचक इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल कर सकें।

चारधाम रूट में 30 से 35 किमी में स्टेशन: अधिक जानकारी देते हुए परिवहन निगम के संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि पहले चरण में चारधाम रूट को कवर किया गया है। इसके तहत 30 से 35 किमी के अंतराल पर कुल 28 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को आसानी से चार्जिंग की सुविधा मिल सके और पर्वतीय क्षेत्रों में यात्री इलेक्ट्रिक वाहन लेने के लिए प्रोत्साहित हों, साथ ही बताया कि चारधाम यात्रा रूटों पर मौजूद जीएमवीएन के गेस्ट हाउसों में ईवी चार्जिंग लगाई गई है, क्योंकि अधिकतर गेस्ट हाउस सड़क किनारे ही मौजूद हैं।

गंगोत्री यात्रा मार्ग पर केंद्र की योजना: संयुक्त परिवहन आयुक्त ने बताया कि भारत सरकार ने ऋषिकेश से गंगोत्री यात्रा मार्ग पर स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है। इसके चलते परिवहन विभाग ने इस मार्ग को छोड़ दिया है। इसके अलावा टीएचडीसी की ओर से कुछ स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन भी लगाए गए हैं। ऐसे में अब दूसरे चरण में कुमाऊं के सभी पर्यटक स्थलों को शामिल किया जा रहा है। इसके लिए 41 स्थान चिह्नित किए गए हैं। इनमें केएमवीएन गेस्ट हाउस, परिवहन निगम बस स्टेशन भी शामिल हैं। दूसरे चरण में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने से संबंधित डीपीआर तैयार है। साथ ही स्थान भी चिह्नित कर लिए गए हैं।

देहरादून में 11 स्थानों के लिए टेंडर खोला गया: परिवहन निगम के साथ ही देहरादून के जिलाधिकारी की पहल पर देहरादून में 11 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए जाने हैं। इस पर देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि पीपीपी मोड पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए टेंडर खोला गया था। साथ ही उस समय कहा गया था कि देहरादून में 11 जगहों पर चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। टेंडर में इस बात पर भी जोर दिया गया था कि 7 से 10 जगहों पर अनिवार्य रूप से चार्जिंग स्टेशन लगाने होंगे। ऐसे में टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद कंपनी का चयन भी कर लिया गया है। कंपनी इसी हफ्ते 8 जगहों पर काम शुरू कर देगी। इस प्रोजेक्ट की खासियत यह है कि देहरादून शहर में ही ईवी चार्जिंग स्टेशन की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति प्रोत्साहन मिलेगा।

उत्तराखंड के इन स्थानों पर लगेंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन

x उधम सिंह नगर जिले में 11 जगहों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाये जाएंगे।

x चंपावत जिले में 4 जगहों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाये जाएंगे।

x पिथौरागढ़ जिले में 7 जगहों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाये जाएंगे।

x नैनीताल जिले में 6 जगहों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाये जाएंगे।

x अल्मोड़ा जिले में 4 जगहों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाये जाएंगे।

x पौड़ी जिले में 4 जगहों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाये जाएंगे।

x देहरादून जिले में 4 जगहों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाये जाएंगे।

x बागेश्वर जिले में एक जगह पर ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा।

ईवी क्रांति का लाभ उठाने के लिए तैयार है अब तमिलनाडु

परिवहन विशेष न्यूज

तमिलनाडु जिसे अक्सर अपने संपन्न ऑटोमोबाइल विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के कारण भारत का डेट्रायट कहा जाता है, ईवी क्रांति का लाभ उठाने के लिए तैयार है। राज्य ने आंतरिक दहन इंजन यानी आईसी इंजन वाहनों से ईवी में संक्रमण के दौरान रोजगार सृजन और पारिस्थितिकी तंत्र विकास के लिए रोडमैप विकसित करने के लिए विश्व बैंक को सूचीबद्ध किया है।

घटनाक्रम से परिचित एक सूत्र के अनुसार विश्व बैंक के अधिकारी आने वाले दिन यानी शुक्रवार को तमिलनाडु के विभिन्न हितधारकों से मिलेंगे, जिनमें तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन (टैंगेडको) और गाइडेंस (निवेशकों की सहायता करने वाली एजेंसी) शामिल हैं ताकि रोडमैप की रूपरेखा तैयार की जा सके। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि विश्व बैंक राज्य में किसी भी परियोजना को वित्तपोषित करेगा या नहीं।

यह पहल भारत के कम कार्बन संक्रमण का समर्थन करने के लिए विश्व बैंक के व्यापक प्रयासों के साथ मेल खाती है। बैंक देश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (बीईएसएस) और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विस्तार के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 1 बिलियन डॉलर की ऋण सहायता देने की योजना बना रहा है। हाल ही में, इसने भारत के कम कार्बन ऊर्जा में बदलाव को गति देने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर के वित्तपोषण को मंजूरी दी।

सूत्र ने कहा, "जब ईवी में बदलाव होगा, तो राज्य में नौकरियों में भारी कमी आएगी। इसका लक्ष्य इस प्रभाव को कम करने और मौजूदा कर्मचारियों को नए कौशल प्रदान करने के लिए एक रणनीति तैयार करना है।"

राज्य सरकार ने ईवी हब के रूप में विकास के लिए छह शहरों - कोयंबटूर, त्रिची, तिरुनेलवेली, मदुरै, सलेम और चेन्नई की पहचान की है। तमिलनाडु के प्राकृतिक लाभों में प्रशिक्षित कार्यबल, सहायक आपूर्तिकर्ताओं का एक मजबूत नेटवर्क, एक जीवंत ऑटो और ऑटो घटक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र और अच्छी तरह से स्थापित बुनियादी ढाँचा और रसद समर्थन प्रणाली शामिल हैं।

तमिलनाडु में पहले से ही भारत के कुल ईवी दोपहिया वाहनों का 70 प्रतिशत उत्पादन होता है, जिसकी वर्तमान विनिर्माण क्षमता 10 मिलियन यूनिट है। उद्योग विशेषज्ञ राज्य की बढ़त का श्रेय ऑटो और ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली 1,500 से अधिक फैक्ट्रियों के पारिस्थितिकी तंत्र को देते हैं, जो नए खिलाड़ियों को सहजता से एकीकृत करने की अनुमति देता है। दोपहिया वाहन खंड में, शीर्ष पांच ईवी निर्माताओं में से तीन - ओला इलेक्ट्रिक, टीवीएस मोटर और एथर एनर्जी तमिलनाडु में स्थित हैं।

तमिलनाडु ने 2024 में महत्वपूर्ण ईवी निवेश आकर्षित किया है। इनमें वियतनामी ईवी निर्माता विनफास्ट की योजनाबद्ध 2 बिलियन डॉलर का प्लांट, टाटा मोटर्स-जेएलआर की 9,000 करोड़ रुपये की सुविधा, हुंडई की 20,000 करोड़ रुपये की विस्तार योजना, रॉयल एनफील्ड की 3,000 करोड़ रुपये की योजनाएं और स्टेलेंटिस की 2,000 करोड़ रुपये की विस्तार योजनाएं शामिल हैं।

अप्रैल में सिट्रोन भारत में घरेलू स्तर पर उत्पादित इलेक्ट्रिक वाहनों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कंपनी बन गई, जिसने तमिलनाडु में निर्मित ई-सी3 मॉडल की शिपिंग की।

ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए 2,000 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन के दिशानिर्देश जल्द ही किए जाएंगे जारी

परिवहन विशेष न्यूज

भारी उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव हनीफ कुरैशी ने मंगलवार, 19 नवंबर को कहा कि सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के समर्थन के लिए नई पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत 2,000 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन वितरित करने के लिए अंतिम दिशानिर्देश एक महीने के भीतर जारी किए जाएंगे।

कुरैशी ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के एक कार्यक्रम में कहा कि मंत्रालय इलेक्ट्रिक कारों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजना के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश भी जारी करेगा, जिसे उसने वैश्विक ईवी निर्माताओं से निवेश आकर्षित करने के लिए इस साल मार्च में अधिसूचित किया था।

पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना, जिसे सितंबर में दो वर्षों में 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अधिसूचित किया गया था, में चार्जिंग बुनियादी ढांचे के लिए 2,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जो इसके पूर्ववर्ती फेम-2 योजना से दोगुना है।

कुरैशी ने कहा कि मंत्रालय ने कई हितधारकों से परामर्श किया है और प्रोत्साहनों की कुल मात्रा के वितरण पर मसौदा दिशानिर्देश तैयार किए हैं। फिलहाल मसौदा दिशानिर्देश राज्य सरकारों के साथ साझा किए गए हैं और मंत्रालय उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है।

उन्होंने कहा, ₹मूल रूप से, प्रत्येक राज्य में मुख्य सचिव के स्तर पर समितियां बनाई जाएंगी, जहां राज्य में चार्जर की मांग को एकत्रित किया जाएगा। प्रत्येक राज्य भारी उद्योग मंत्रालय को एक प्रस्ताव भी भेजेगा, और फिर दोनों को मंजूरी दी जाएगी।"

उन्होंने कहा कि शहर में ईवी की संख्या और राजमार्गों से गुजरने वाले वाहनों की संख्या जैसे मापदंडों के आधार पर प्रोत्साहन वितरित किए जाएंगे। कुरैशी ने कहा, ₹हम इस आधार पर प्राथमिकता तय करेंगे कि किसी राज्य के पास ईवी नीति है या नहीं, उनके पास अपने कुछ प्रोत्साहन हैं या नहीं। क्योंकि हमें 2,000 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्ताव मिल सकते हैं।"

अंतिम दिशानिर्देश अपस्ट्रीम बुनियादी ढांचे के लिए प्रोत्साहन भी आवंटित करेंगे, जिसे बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा विकसित किया जाएगा, क्योंकि उनमें से कई वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

कुरैशी ने कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीएमईपीसीआई) के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश, जिसे मार्च में अधिसूचित किया गया था, 3-4 सप्ताह के भीतर जारी कर दिए जाएंगे। यह योजना अनिवार्य रूप से 35,000 डॉलर से अधिक कीमत वाले कार मॉडल पर आयात शुल्क को 100 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर देती है, बशर्ते कि निर्माता स्थानीय कारखाना स्थापित करने में 500 मिलियन डॉलर का निवेश करने का वादा करे।

वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, यह योजना "प्रतिष्ठित वैश्विक ईवी निर्माताओं द्वारा ई-वाहन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए तैयार की गई है" और इसका उद्देश्य "भारतीय उपभोक्ताओं को नवीनतम तकनीक तक पहुंच प्रदान करना, मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देना, ईवी खिलाड़ियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर ईवी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, कच्चे तेल के आयात को कम करना और वायु प्रदूषण को कम करना" है।

पीएम ई-ड्राइव योजना का लक्ष्य मांग प्रोत्साहन के माध्यम से लगभग 25 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया, 3 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया और 14,000 इलेक्ट्रिक बसों का समर्थन करना है। हालाँकि, इसके पूर्ववर्ती फेम-2 योजना की तुलना में, नवीनतम सब्सिडी में प्रोत्साहन काफी कम हैं। वे एक महत्वपूर्ण चूक भी करते हैं- इलेक्ट्रिक कारें।

कुरैशी ने कहा, ₹एक विचारधारा का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अग्रिम मांग सब्सिडी के रूप में कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। इसके बजाय, कराधान लाभ होना चाहिए और पर्याप्त चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। यदि पर्याप्त चार्जिंग है और लोगों को कोई चिंता नहीं है, तो यह उनके लिए जीवन को आसान बना देगा और वे अपने दम पर ईवी खरीदेंगे। और आंशिक रूप से, यही हमने पीएम ई-ड्राइव योजना में अपनाया है।₹

उन्होंने कहा, ₹फेम-2 योजना में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर परिव्यय 1,000 करोड़ रुपये था, जो 5 साल की योजना थी। अब पीएम ई-ड्राइव योजना में परिव्यय 2,000 करोड़ रुपये है, जो केवल 2 साल की योजना है। इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों के लिए 22,100 चार्जर होंगे। उच्च घनत्व वाले यातायात वाले शीर्ष 40 शहरों और शीर्ष 50 राजमार्गों की एक अस्थायी सूची है। दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए चार्जर लगभग 48,000 होंगे और बसों और ट्रकों के लिए लगभग 1,800 चार्जर होंगे, ये सभी उच्च घनत्व वाले गलियारों के लिए होंगे।₹

इस कार्यक्रम में काइनेटिक ग्रीन एनर्जी एंड पावर सॉल्यूशंस लिमिटेड की सीईओ और फिक्की में इलेक्ट्रिक व्हीकल कमेटी की अध्यक्ष सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी ने कहा कि रिप्लेसमेंट बैटरी और चार्जिंग सेवाओं पर जीएसटी को मौजूदा 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाना चाहिए। ₹इससे हमारे उपभोक्ताओं के लिए चार्जिंग और भी सस्ती हो जाएगी और इससे बैटरी को बदलना और भी सस्ता हो जाएगा। इससे OEM को उल्टे शुल्क ढांचे के कारण फंड ब्लॉकेज को कम करने में भी मदद मिलेगी।

उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत प्रोत्साहन समाप्त होने लगे हैं। ₹हमारा मानना है कि इस योजना के तहत आवंटन पहले से ही समाप्त होने लगे हैं। तिपहिया वाहनों के लिए, हमारे पास पहले से ही पैसे खत्म हो चुके हैं और इसका मतलब है कि इस योजना को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। हम एमएचआई से आग्रह करना चाहेंगे कि वह इस योजना के विस्तार पर विचार करे और इस हरित सपने के लिए अधिक बजट आवंटित करे।"

जवाब में प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर ने कहा, ₹तीन पहिया वाहनों के लिए हमारी सब्सिडी खत्म हो गई है, इसलिए मुझे लगता है कि यह एक सफलता है, यह विफलता नहीं है। लेकिन कल सब्सिडी बहाल कर दी गई, इसलिए ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं। बस इतना है कि पहले साल में एक खास संख्या के लिए मंजूरी दी गई थी और हमने कुछ ही महीनों में ऐसा कर दिया।"

कृत्रिम बुद्धि का बढ़ता प्रभाव

विजय गर्ग

नई तकनीकों का उपयोग करने वाले अभिनव उत्पाद और सेवाएं सौंदर्य और कल्याण क्षेत्र में हलचल मचाने लगी हैं। परिणामस्वरूप, पारंपरिक कौशल को मजबूत करने और आधुनिक तकनीकी कौशल जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ऐप विकास, ट्राई- ऑन सेवाओं के लिए संवर्धित वास्तविकता, डेटा एनालिटिक्स और उन्नत ग्राहक जुड़ाव रणनीतियों के साथ संयोजित करने की आवश्यकता है।

नई तकनीकों का उपयोग करने वाले अभिनव उत्पाद और सेवाएं सौंदर्य और कल्याण क्षेत्र में हलचल मचाने लगी हैं। परिणामस्वरूप, पारंपरिक कौशल को मजबूत करने और आधुनिक तकनीकी कौशल जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ऐप विकास, ट्राई-ऑन सेवाओं के लिए संवर्धित वास्तविकता, डेटा एनालिटिक्स और उन्नत ग्राहक जुड़ाव रणनीतियों के साथ संयोजित करने की आवश्यकता है। एआई ने सौंदर्य और कल्याण क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है, खासकर जब अनुकूलन और वैयक्तिकरण की मांग बढ़ी है। यह प्रवृत्ति विविध ग्राहक वरीयताओं, जीवन शैली, शरीर के प्रकार और आनुवंशिक कारकों को दर्शाती है। माइक्रोसाफ्ट टीमों के लिए मेवेलिन केएआई संचालित मेकअप फ़िल्टर के बारे में हाल ही में आई खबरों ने सौंदर्य क्षेत्र में एआई की भूमिका पर चर्चाओं को फिर से हवा दे दी है। यह पता लगाना महत्वपूर्ण है। कि एआई किस तरह से उद्योग को बदल रहा है और नवीनतम विकास पर अपडेट रहना चाहिए। 2020 में एआई का उपयोग करने वाले वैश्विक सौंदर्य उद्योग का मूल्य 216.12 मिलियन था और 2027 तक 1.26 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। एक उद्योग रिपोर्ट बताती है कि 2021 से 2027 तक सौंदर्य क्षेत्र में एआई की वार्षिक वृद्धि दर 33.2 प्रतिशत होने की उम्मीद है।

कई प्रयोगशालाओं ने एआई- संचालित त्वचा परामर्श उपकरण विकसित किए हैं जो त्वचा की उम्र बढ़ने का विश्लेषण करने के लिए संवर्धित वास्तविकता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एकीकृत करते हैं। ये उपकरण उम्र बढ़ने के संकेतों की पहचान कर सकते हैं और त्वचा की मजबूती का आकलन कर सकते हैं, जिससे आगे की गिरावट को रोकने के लिए अनुरूप त्वचा देखभाल सिफारिशें मिल सकती हैं। उनके एल्गोरिदम 10,000 छवियों और 15 वर्षों की त्वचाविज्ञान विशेषज्ञता पर आधारित हैं। उपयोगकर्ता एक सेल्फी ले सकते हैं और अपनी त्वचा

की स्थिति का अनुमान लगाने के लिए अपनी उम्र और त्वचा का प्रकार प्रदान कर सकते हैं और साथ ही एक व्यक्तिगत विश्लेषण भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर उन्हें अनुकूलित त्वचा देखभाल नुस्खे प्राप्त होंगे। एआई त्वचा की स्थितियों का विश्लेषण करने, व्यक्तिगत त्वचा देखभाल और स्वास्थ्य दिनचर्या की सिफारिश करने और यहां तक कि रुझानों की भविष्यवाणी करने में सहायता करता है, जिससे अंततः उत्पाद विकास और ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि होती है। मुहांसे दुनिया भर में एक आम समस्या है, जो 80 प्रतिशत किशोरों और 40 प्रतिशत वयस्कों को प्रभावित करती है। एआई के साथ, विभिन्न जातीय त्वचा प्रकारों का प्रतिनिधित्व करने वाली 6,000 छवियों का एक डेटाबेस, मुहांसे से पीड़ित लोगों के लिए सटीक विश्लेषण और व्यक्तिगत नियमित अनुशंसाओं को सक्षम बनाता है। यह अभूतपूर्व एआई तकनीक वास्तविक त्वचा विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन की गई 10,000 प्रामाणिक छवियों की लाइब्रेरी से आकर्षित होती है, जो आठ नैदानिक मापदंडों और त्वचा के विभिन्न प्रकारों में लगभग 97 प्रतिशत की सटीकता दर प्राप्त करती है।

लगातार विकसित हो रहे सौंदर्य और कल्याण उद्योग में, जहां नवाचार आत्मविश्वास और आत्म-अभिव्यक्ति को बढ़ावा देता है, एआई पहले से कहीं अधिक प्रभावी और व्यक्तिगत उत्पाद निर्माण बनाने में एक शक्तिशाली सहयोगी बन गया है। अपने विविध अनुप्रयोगों और क्षमताओं का लाभ उठाकर एआई एक क्रांति ला रहा है जो सौंदर्य और कल्याण उत्पादों के विकास, व्यक्तिगतकरण और विपणन के तरीके को बदल रहा है। ट्रेंड स्पॉटिंग से लेकर सटीक उत्पाद निर्माण तक, एआई सौंदर्य उद्योग को रोमांचक और अभूतपूर्व तरीकों से नया रूप दे रहा है। निर्माण प्रक्रिया में एआई को एकीकृत करने से उत्पाद की प्रभावशीलता भी सुनिश्चित हो सकती है। एआई एल्गोरिदम यह अनुकरण कर सकते हैं कि त्वचा द्वारा अवयवों को कैसे अवशोषित और चयापचय किया जाता है, संभावित अवांछित अंतः क्रियाओं या दुष्प्रभावों की पहचान करते हुए ।

यह दृष्टिकोण नए उत्पादों को बाजार में लाने से जुड़े जोखिमों को कम करता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ता अपनी भलाई से समझौता किए बिना इष्टतम परिणाम करें। परंपरागत रूप से, स्किनकेयर उत्पादों को एक ही आकार- फिट- सभी दृष्टिकोण के साथ विकसित किया गया है, जो अक्सर व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की अनूठी जरूरतों को पूरा करने में विफल रहता है। एआई त्वचा के प्रकार, आयु, पर्यावरणीय कारकों और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं सहित विभिन्न डेटा बिंदुओं का विश्लेषण करके इस पद्धति को बदलता है।

- संचालित उपकरणों का उपयोग करके, ब्रांड प्रत्येक ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित स्किनकेयर उत्पाद बना सकते हैं। उदाहरण के लिए एआई एल्गोरिदम फ़ोटो और प्रश्नावली के माध्यम से उपयोगकर्ता की त्वचा की स्थिति का आकलन कर सकते हैं, सक्रिय अवयवों की विशेष सांद्रता वाले उत्पादों की सिफारिश या निर्माण कर सकते हैं जो व्यक्तिगत त्वचा संबंधी चिंताओं को संबोधित करते हैं। इसके अतिरिक्त, एआई आणविक संरचनाओं का विश्लेषण करके यह अनुमान लगा सकता है कि नए यौगिक मानव त्वचा के साथ कैसे बातचीत करेंगे, जिससे पारंपरिक परीक्षण और त्रुटि विधियों के समय और लागत में काफी कमी आएगी।

एआई सिस्टम प्रत्येक व्यक्ति की जरूरतों के अनुरूप उपयुक्त सामग्री, उत्पाद और स्किनकेयर रूटीन की सिफारिश करता है। यह ब्रांडेड उत्पादों का सुझाव भी दे सकता है जो सौंदर्य और कल्याण उद्योग में विशिष्ट स्थितियों को संबोधित करते हैं, जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्राहक की प्राथमिकताओं से गहराई से जुड़ना है। जैसे-जैसे तकनीक विकसित होती जा रही है, यह ऐसे समाधानों का वादा करती है जो भविष्य में दिखावट और सेहत दोनों को बढ़ाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका डेटा निजी रहता है; इसे संग्रहीत नहीं किया जाता है और केवल आप ही परिणाम देख सकते हैं जब तक कि आप अपनी जानकारी दूसरों के साथ साझा नहीं करना चुनते। सौंदर्य और कल्याण उद्योग में सफलता के लिए एक व्यक्तिगत अनुभव महत्वपूर्ण है। एआई तकनीक प्रत्येक ग्राहक की अनूठी प्राथमिकताओं की पहचान करने और उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे-जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, सौंदर्य कंपनियों से ऐसी अभिनव सेवाएँ शुरू करने की अपेक्षा की जाती है जो ग्राहकों के साथ संपर्क को बढ़ाएँ और सौंदर्य बाज़ार के वैश्विक विकास में योगदान दें। इन तकनीकी प्रगति के साथ-साथ ऑनलाइन सेवाएँ तेज़ी से विकसित रही हैं। वेबसाइट, आकर्षक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और ऑनलाइन मार्केटप्लेस का महत्व बढ़ रहा है। सौंदर्य और व्यक्तिगत देखभाल क्षेत्र में ऑनलाइन राजस्व का हिस्सा, जो 2017 में लगभग 4.6 प्रतिशत था, 2025 तक बढ़कर 18.2 प्रतिशत होने का अनुमान है। सौंदर्य और कल्याण उद्योग का भविष्य एक ऐसे सर्वव्यापी अनुभव पर निर्भर करेगा जो ऑनलाइन और ऑफ़लाइन इंटरैक्शन को सहजता से एकीकृत करता है, उपभोक्ता अनुभव को बढ़ाने के लिए डिजिटल उपकरणों की एक श्रृंखला का उपयोग करता है। ब्यूटी रिटेल में वर्चुअल ट्राई- ऑन और परामर्श मानक बन गए हैं; हालाँकि, मानवीय कनेक्शन को दोहराना एक चुनौती बनी हुई है। ऑनलाइन प्रभावशाली व्यक्ति और मुझे दिखाओ कैसे सामग्री लोकप्रियता प्राप्त कर रही है क्योंकि उपभोक्ता उन सेवाओं में महारत हासिल करना सीख रहे हैं जो वे पहले पेशेवरों से चाहते थे। इसके अतिरिक्त, फेसबुक लाइव और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग युवा उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण रूप से आकर्षित करती है। भारत में सौंदर्य और कल्याण उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप की तुलना में दोगुनी तेजी से बढ़ रहा है। उपभोक्ताओं की बढ़ती जागरूकता और आकांक्षा ने सौंदर्य और स्वास्थ्य उत्पादों और सेवाओं पर खर्च में वृद्धि की है। सौंदर्य और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों पर प्रति व्यक्ति खर्च 2017 में 450

रुपये प्रति वर्ष से बढ़कर 2022 में 684 रुपये हो गया, और 2025 तक इसमें और वृद्धि होकर 772 रुपये होने का अनुमान है। आज के उपभोक्ता अद्वितीय अनुभव की मांग करते हैं, जिससे पारंपरिक दृष्टिकोण कम प्रभावी हो जाते हैं। सुविधा और ऑन डिमांड सेवाओं के लिए बढ़ती प्राथमिकता है, जो कामकाजी पेशेवरों के तेज-तर्रार जीवन में आवश्यक हो गई है। नतीजतन, सौंदर्य और स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यबल के भीतर हस्तांतरणीय कौशल की बढ़ती आवश्यकता है, क्योंकि ग्राहक सेवा विशेषज्ञता की मांग अधिक होती जा रही है।

सतह के पार कला

विजय गर्ग

हमेशा से कला के विभिन्न माध्यमों ने बदलाव की अलख जगाकर जनमानस को झकझोरा है। कितने ही नारे, गीत, चित्र, कहानियां, सिनेमा ऐसे हैं जो न होते तो क्रांतियों के चक्के की गति थोड़ी धीमी जरूर हो जाती । अब चाहे वह पाब्लो पिकासो की पेंटिंग 'गुएर्निका', जो स्पेन के गृहयुद्ध की भयावहता के खिलाफ एक शक्तिशाली युद्ध - विरोधी प्रतीक बन गई, हो या फिर 'वंदे मातरम्' की वह जादुई धुन और इंकलाबी बोल, जिसने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारतीयों में राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को तूल दिया। लेकिन आमतौर पर कला और उसके प्रभाव के बीच असंगति के कई उदाहरणों से भी हमारा सामना होता रहता है। अक्सर कला को जिस समाज का दर्पण कहा जाता रहा है, वह न जाने कब और क्यों शीशे में झांकने के बजाय महज उसकी चमक और बनावट को तरजीह देने लगा। यह कला के संदर्भ में उसकी कसौटी पर एक सवाल की तरह है, जिसका जवाब खोजने की कोशिश में कला का प्रेमी लगा रहता है ।

दरअसल, कला मानक विश्वासों को चुनौती देती है । यह संवाद को प्रोत्साहित कर आलोचनात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है । पर हमने शायद वह सुदूर कोना तलाश लिया है जहां बैठ कर हम कला से अछूते रहकर भी उसे घंटों निहार सकते हैं। लोग किसी रचना के सौंदर्य या कहन को पसंद करने के बावजूद उसके मूल संदेश के प्रतिरोधी बने दिखते हैं। कला - उपभोग और आत्मसात के बीच यह विभाजन एक बड़ी समस्या को करता है। लोग अपनी पूर्वधारणाओं के अनुरूप कला को मनोगत करते हैं। ऐसे लोग कला को विकास का उत्प्रेरक बनाने के बजाय इसे अपने जीवन के पूर्वनिर्धारित विश्वासों को कायम रखने का माध्यम बना लेते हैं। और जब जब धारणा पर आग्रह हावी हो जाए, तो आकलन का निष्कर्ष क्या होगा ?

कला के साथ यह चयनात्मक जुड़ाव व्यापक सामाजिक चाल-चलन की बानगी है, जिसमें लोग आत्म-परीक्षण और परिवर्तन से कन्नी काटते हैं। इसका एक कारण 'संज्ञानात्मक असंगति' (काग्निटिव डिसोनेंस) की मनोवैज्ञानिक अवधारणा में निहित है। जब कोई व्यक्ति एक साथ दो विरोधाभासी विचारों, विश्वासों या मूल्यों को धारण करता है, तो उसे असहजता होती है । इस असुविधा को कम करने के लिए वह प्रचलित विश्वास को तर्कसंगत मान लेता है। जब लोग विचारोत्तेजक कला का उपभोग करते हैं, तब अवचेतन में उन तत्त्वों को नजरअंदाज या खारिज कर देते हैं जो आंतरिक संघर्ष का कारण बनते हैं। एक युवक ने नेटफ्लिक्स की 'अनआर्थोडाक्स' सीरीज बड़े चाव से देखी । यह सीरीज एक महिला की कहानी है जो अपने कट्टर रूढ़िवादी यहूदी समुदाय से आजादी और स्वायत्तता की खोज में भाग जाती है। सीरीज एक कठोर, पितृसत्तात्मक धार्मिक समुदाय में जीवन की कठिनाइयों और इससे बाहर निकलने की चुनौतीपूर्ण यात्रा को दिखाती है। वह युवक इस कहानी से गहरे तौर पर प्रभावित हुआ, लेकिन वह एक कट्टर धार्मिक व्यक्ति होते हुए भी कट्टरतावाद की कोई आलोचना नहीं कर पाया । न ही उसने अपने सख्त धार्मिक विश्वासों पर कोई सवाल उठाया। इसी तरह, एक महिला के स्कूल के दिनों में उनके दोस्तों ने 'रीढ़ की हड्डी' नामक एक एकांकी का मंचन किया था । एकांकी का उद्देश्य उस सामाजिक ढर्रे पर तंज कसना था, जिसमें शादी के लिए लड़कियों को भेड़-बकरियों की तरह तौला और बेचा जाता है । इसे दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया, जिसमें शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थी शामिल थे। हालांकि कुछ वर्षों बाद उन सभी लड़कियों की शादी उन्हीं बेढब रूढ़ियों के तहत रचा दी गई ।

वृहत और दैनिक पैमाने पर कला के संदेश पर कार्रवाई न करने के कई उदाहरण मौजूद हैं। मसलन, वह व्यक्ति जो पर्यावरण पर आधारित विज्ञापनों या वृत्तचित्रों से प्रभावित होता है, लुप्तप्राय

प्रजातियों या पिघलते ग्लेशियरों या हिमनदों को देखकर आंसू बहाता है, फिर भी अपना जीवन यथावत बिताता है। वह अपने सामने यह होते रहने की असली वजहों की पड़ताल की कोशिश भी नहीं करता। या वह शख्स जो मजदूरों की दुर्दशा पर लिखी गई कविताओं को साझा कर उनकी सुंदरता और भावनात्मक अपील की तारीफ करता है, लेकिन अपने घरेलू कामगारों के साथ बुरा व्यवहार या उन्हें कम भुगतान करता है । कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार की निंदा करने या सामाजिक असमानता पर प्रकाश डालने वाली फिल्म की सराहना कर खुद अपने कार्यस्थल पर अनैतिक गतिविधियों में लिप्त सकता है या कर की चोरी कर सकता है। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि लोग सामाजिक रूप से जागरूक कला को सराह तो सकते हैं, लेकिन उसके मायनों को अपने जीवन में उतार नहीं सकते। ऐसी स्थिति में कला के डिब्बे पर चमचमाता ढक्कन लग जाता है, जबकि उसके भीतर रखे बदलाव के बीज पड़े-पड़े धूल फांकते हैं ।

कला, जब सिर्फ रिझाती है, कुछ सुझाती नहीं, तब अपनी गहनता और पहचान खो देती है । यह उपभोक्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे कला के सतही आकर्षण के पार जाएं और उसके पीछे के अर्थ और संदर्भ को खोजें, थामें । किसी भी रचना में मौजूद मूल तत्त्वों पर गौर करके उसकी व्यावहारिकता सुनिश्चित करना ही उस रचना की पुष्टि हो सकती है।

वास्तविक दुनिया के कौशल के लिए शिक्षा को नया स्वरूप देना

विजय गर्ग

कमाई, बचत और पैसे के प्रबंधन पर व्यावहारिक पाठों को एकीकृत करके, शिक्षा छात्रों को वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के लिए बेहतर ढंग से तैयार कर सकती है यह कहना सत्य है कि दुनिया तेजी से जटिल होती जा रही है और इससे निपटने के तरीकों को संरचित और समझने की जरूरत है। यह अकेले ही उस दुनिया में जिस तरह से काम कर रहा है उस पर बढ़ते दुःख और घबराहट से बचाएगा। वित्त के क्षेत्र का एक उदाहरण स्थिति को स्पष्ट कर सकता है। यह स्पष्ट बात है कि हर किसी को जीवित रहने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है और यदि वित्त कहीं से अर्जित नहीं किया जाता है तो उसे प्राप्त करना ही पड़ता है। वित्त को समझने या कमाई करने के इस व्यवसाय के लिए यह समझने की क्षमता की आवश्यकता होती है कि वित्त क्या है और इसे कैसे अर्जित किया जा सकता है। वित्त कई आकार और रंगों में आता है। सभी वित्त में एक सामान्य कारक यह है कि यह किसी के प्रयास के लिए एक मौद्रिक मूल्य डाल रहा है और यह सिस्टम को चालू रखने के लिए किए गए कार्यों के लिए मुआवजा है। वित्त प्रयास और उसके मुआवजे के बीच समीकरण स्थापित करता है और बदले में वित्त खरीदारी और खरीद से परे जीवन की जरूरतों को प्राप्त करने दोनों के लिए एक उपकरण बन जाता है। ऐसा करने के लिए, किसी को मुद्रा, उसकी तुल्यता और प्रयास में मुद्रा को कैसे मापा जाता है, यह समझने की आवश्यकता है। यह हमारे प्रचलित स्कूल और कॉलेज प्रणाली की पहेली में से एक है कि इन मामलों को शायद ही कभी पाठ्यक्रम के माध्यम से या औपचारिक स्थिति में समझाया जाता है। अवलोकन के माध्यम से वित्त के बारे में बहुत कुछ सीखा जाता है और जिस घरेलू माहौल में व्यक्ति बड़ा हुआ है, वह परिचालन जीवन में लेन-देन में परिवर्तित हो जाता है और व्यक्ति अपने जीवन में काफी पहले ही सीख लेता है कि पैसा कमाने के लिए उसके पास क्षमताएं होनी चाहिए और इसलिए वित्त से निपटना चाहिए। प्रत्येक प्रणाली में प्रयासों और मुआवजे के बीच समानता के अपने तरीके होते हैं और जो ताकतें इसे निर्धारित करती हैं उन्हें अक्सर बाजार ताकतों के रूप में जाना जाता है। यह अपने आप में एक कला है जिसे जीवन कभी-कभी सरलता से और बार-बार परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से सिखाता है। इस प्रकार, यह है कि वित्त न केवल मुश्किल है, बल्कि यह समझने में मदद करता है और फिर भी यह किसी के भी जीवन की आधारशिलाओं में से एक है। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए, यह महसूस करने की जरूरत है कि वित्त में कुछ बुनियादी घटक होते हैं जैसे कमाई, बचत, निवेश, मूर्त संपत्ति में परिवर्तित करना और भी बहुत कुछ। प्रत्येक क्षेत्र समय के साथ सीखने और वास्तव में किसी के अस्तित्व की खुशी या अन्यथा का एक विशेष क्षेत्र बन गया है।

स्कूल की उच्च कक्षाओं में वित्त में कुछ ताकतें होती हैं जहां कुछ बुनियादी अवधारणाओं को समझाया जाता है और वित्त पर कुछ आवश्यक मूलभूत विचार साझा किए जाते हैं। जरूरत इस बात की है कि इसे व्यावहारिक दिशा दी जाए और फील्डवर्क के माध्यम से लोगों को वित्त का महत्व और मानव जीवन में इसकी केंद्रीय भूमिका सिखाई जाए। अधिकांश कक्षाएँ सोच के उस स्तर तक, या सोचने के उस तरीके तक नहीं पहुंची हैं, जिसका बहुत सरल अर्थ है कि अधिकांश लोग वित्त की अनिवार्यताओं और जीवन की नींव के बीच संबंध को समझे बिना ही अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर लेते हैं। स्थिति तब और अधिक जटिल हो जाती है जब कोई कॉलेज या विश्वविद्यालय स्तर से स्नातक होता है और तब तक जब तक वह वित्त में एक विशिष्ट पाठ्यक्रम नहीं कर रहा होता है, वह वित्त के बारे में स्कूल में जो सीखा है उससे आगे कभी कुछ नहीं सीख सकता है। यह एक नुकसान है क्योंकि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, स्कूल में वित्त के बारे में जो पढ़ाया जाता है वह वित्त के अभ्यास में बहुत दूर तक नहीं जाता है।

हर किसी को यह जानने की जरूरत है कि प्रबंधन कौशल में किसी के मूल्य के बीच क्या संबंध हैऔर जानकारी और पर्यावरण द्वारा वित्तीय दृष्टि से इसकी भरपाई कैसे की जाती है। यह अपने आप में एक पेचीदा प्रस्ताव है और, जैसा कि पहले सुझाव दिया गया है, इस पर फील्डवर्क की आवश्यकता है। फिर वित्त के अंतिम क्षेत्र हैं जिन्हें व्यावहारिक दुनिया के सामने लाए बिना सीखा नहीं जा सकता और यह ऐसा मामला नहीं है जिसे कक्षा में लाया जा सके। इसके अलावा, एक सामान्य शिक्षा प्रणाली में, फिर से अंतराल होते हैं जहां यह सीखना डिफ़ॉल्ट रूप से होता है और लोगों को परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से खुद के लिए भुगतान करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इससे न केवल अत्यधिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं बल्कि किसी न किसी प्रकार की जटिलताएँ भी उत्पन्न होती हैं। किसी की कमी हो सकती है या किसी को पता नहीं हो सकता है कि सेवाएं, कई मामलों में, किसी प्रकार के मुआवजे के बिना प्रदान नहीं की जा सकती हैं और मुआवजा अक्सर पैसे के रूप में होना चाहिए। लोगों को धन, वित्त और प्रयास के बीच संबंध समझाना एक सार्थक तरीका होगा। ऐसा दृष्टिकोण न केवल स्कूलों बल्कि कॉलेजों के पाठ्यक्रम को भी किसी के जीवन में सार्थक और अधिक व्यावहारिक बनाने में मदद करेगा। जैसा कि मामला है, यदि कोई भौतिकी, रसायन विज्ञान, इतिहास, मनोविज्ञान, भूगोल, या किसी अन्य चीज़ में विशेषज्ञता रखता है, तो उसे शायद ही पता चलता है कि तथाकथित विशेषज्ञता से परे, एक सामान्य शिक्षा की आवश्यकता है। यह सामान्य शिक्षा दूसरों के प्रति व्यवहार, स्वयं का प्रबंधन, आय को समझना, व्यय को समझना, बचत को समझना आदि हो सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो, वयस्कता में प्रवेश करने और आर्थिक रूप से व्यवहार्य इकाई बनने से पहले सीखने की सीमा पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जैसा कि पहले संकेत दिया गया है, इसमें से अधिकांश परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से हो रहा है, एक विधि को अपनाकर; यह कुछ मामलों में काम करता है लेकिन अन्य में नहीं। किसी के वयस्क होने और खुले समुद्र में फेंके जाने से पहले औपचारिक आदानों के माध्यम से वास्तविक जीवन में समायोजन के लिए खजाने को कम करने की स्पष्ट आवश्यकता है - जैसे कि यह स्वयं की देखभाल करने के लिए था।

समय आ गया है कि शिक्षा, आत्म-निर्माण और शिक्षण का एक ऐसा दर्शन स्थापित किया जाए जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और जीवन की आवश्यकताओं से जुड़ा हो। ऐसे मामलों पर कुछ बुनियादी सोच-विचार करने का यह सही समय है और यह काम जितनी जल्दी किया जाए, उतना बेहतर होगा। इसी तरह, उसे बचपन, किशोरावस्था और जीवन के अन्य चरणों के माध्यम से प्रौद्योगिकी की प्रकृति और सामग्री के बारे में एक व्यक्ति बनाने में समान प्रतिबिंब की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रौद्योगिकी हमारे जीवन के हर पहलू को छूती है, न केवल उस चश्मे से जो किसी को अपनी दृष्टि को सही करने के लिए पहनना पड़ता है, बल्कि हर उस चीज़ तक जो किसी की आजीविका और अस्तित्व का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। मूल प्रकृति को शामिल करना और समझना स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में प्रौद्योगिकी पर भी ध्यान देने की जरूरत है। हालाँकि, यह एक ऐसा विषय हो सकता है जिस पर अलग से और स्वतंत्र रूप से विचार करने की आवश्यकता है।

घर का सपना होगा साकार, पीएम आवास योजना के लिए 25 राज्यों का केंद्र के साथ समझौता

परिवहन विशेष न्यूज

केंद्र ने इस बार एमओयू में लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता के लिए मानक कड़े किए गए हैं। राज्यों से यह अपेक्षा की गई है कि वे अनिवार्य रूप से किफायती आवासों के लिए एक नीति बनाएं। शहरी भारत के एक करोड़ लोगों को पक्के घर उपलब्ध कराने के लिए पीएम आवास योजना 2.0 का शुरुआत की गई है। ये घर अगले पांच साल में बनने हैं।

नई दिल्ली। शहरी क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना पर राज्यों ने अच्छा उत्साह दिखाया है। योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार के साथ सहमति पत्र पर 25 से अधिक राज्यों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके पहले सरकार 147 बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भी इससे जोड़ चुकी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने पीएम आवास योजना के क्रियान्वयन के तौर-तरीकों को स्पष्ट करने के लिए अब तक दो राष्ट्रीय कार्यशालाएं आयोजित की हैं, जिसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इसी दौरान राज्यों ने एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए। यह इसलिए अहम है, क्योंकि इस बार एमओयू में लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता के लिए मानक कड़े किए गए हैं। इसके अलावा राज्यों से यह अपेक्षा की गई है कि वे अनिवार्य रूप से किफायती आवासों के लिए एक नीति बनाएं। शहरी भारत के एक करोड़ लोगों को पक्के घर उपलब्ध कराने के लिए पीएम आवास योजना 2.0 का शुरुआत की गई है। यह घर अगले पांच साल में बनने हैं और इन पर करीब दस लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे।

मंत्रालय राज्यों के साथ एमओयू के बाद लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार योजना की शुरुआत में ही लगभग सभी राज्यों का इसके लिए आगे आना बड़ी बात है। दिसंबर से लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। इसके लिए राज्यों को अपने-अपने स्तर पर मानक तय करना है और इसी के अनुरूप वे अपनी मांग सामने रखेंगे।

18 से 20 लाख घरों का आवंटन

सूत्रों के अनुसार पहले साल 18 से 20 लाख घरों का आवंटन हो सकता है। इस योजना को रोजगार सृजन के नजरिये से भी काफी अहम माना जा रहा है। घरों के निर्माण में तीन करोड़ से अधिक रोजगार सृजन होने की उम्मीद की जा रही है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कार्यशाला में कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए जवाबदेही और जिम्मेदारी की जरूरत है, इसमें कमी नहीं होनी चाहिए।

मनोहर लाल ने कहा कि इस योजना के तहत किफायती किराये के आवासों का जिक्र करते हुए कहा कि कामकाजी महिलाओं और औद्योगिक श्रमिकों को पर्याप्त किफायती किराये के आवास उपलब्ध कराने के लिए पहली बार एक आवास योजना में अलग वर्टिकल के रूप में पेश किया गया है।

मंत्रालय में हाउसिंग फॉर आल के संयुक्त सचिव और मिशन डायरेक्टर कुलदीप नारायण ने कहा कि पीएम आवास योजना के पहले चरण से बहुत कुछ सीखने के बाद इस योजना का दूसरा चरण आरंभ किया गया है। सुधारों के लिए राज्यों के पास कई विकल्प हैं। हर राज्य के पास किफायती आवास नीति होना जरूरी है।

'ट्रंप की नीतियों से भारत के आईटी सेक्टर को होगा फायदा', विप्रो चेयरमैन ने बताया कैसे

विप्रो के कार्यकारी अध्यक्ष रिशद प्रेमजी ने मंगलवार को बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में कहा कि अमेरिका में ट्रंप का राष्ट्रपति पद प्रो-बिजनेस और प्रो-ग्रोथ और तकनीकी सेवा उद्योग के लिए अच्छा होगा।उनका कहना है क भारतीय कंपनियां और निवेशक देश के 254 अरब डॉलर के आईटी सेवा उद्योग पर उनकी नीतियों के प्रभाव का आकलन करने के लिए व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी पर कड़ी नजर रखेंगे।

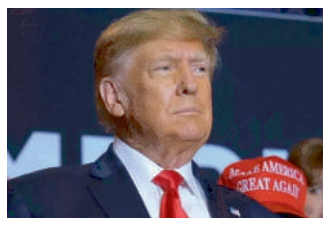

नई दिल्ली। ट्रंप ने अमेरिका में दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत के बड़े आर्थिक जानकारों का कहना है कि ट्रंप भारत के लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। इसी को आगे बढ़ाते हुए विप्रो के कार्यकारी अध्यक्ष रिशद प्रेमजी ने मंगलवार को बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में कहा कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति पद प्रो-बिजनेस और प्रो-ग्रोथ और तकनीकी सेवा उद्योग के लिए अच्छा होगा।

भारत के पास 254 अरब डॉलर का आईटी सेवा उद्योग

रिशद प्रेमजी का कहना है क भारतीय कंपनियां और निवेशक देश के 254 अरब डॉलर के आईटी सेवा उद्योग पर उनकी नीतियों के प्रभाव का आकलन करने के लिए व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी पर कड़ी नजर रखेंगे। आगे प्रेमजी ने कहा कि ट्रंप के राष्ट्रपति पद के दौरान कम करों और विनियमों पर बातचीत आगे बढ़ सकती है और व्यवसाय के लिए और ग्राहक कैसे खर्च करेंगे, इसके लिए अच्छा संकेत है।

आईटी कंपनियों को मुद्रास्फीति के दबावों के बारे में सतर्क रहना चाहिए

संभावित कॉर्पोरेट कर दर में कटौती और आसान व्यापार नियमों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार बहुत व्यवसाय समर्थक और विकास समर्थक है, जो हमारे सभी ग्राहकों की मदद करती है, जो अंततः भारत और दुनिया भर में भागीदारों की मदद करती है। आगे प्रेमजी ने कहा कि आईटी कंपनियों को मुद्रास्फीति के दबावों के बारे में सतर्क रहना चाहिए, विशेष रूप से टैरिफ के संबंध में और आव्रजन नीतियां कैसे विकसित होती हैं।

एच-1बी वर्क वीजा पर ट्रंप से भारतीयों को उम्मीदें

केयरएज रेटिंग्स के एक नोट में कहा गया है कि आउटसोर्सिंग पर सख्त अमेरिकी नीतियों और एच-1बी वर्क वीजा पर प्रतिबंधों से भारत के आईटी क्षेत्र पर असर पड़ सकता है, जो अमेरिकी बाजार पर बहुत अधिक निर्भर करता है। नोट में कहा गया है कि भारतीयों को संयुक्त राज्य अमेरिका से सबसे अधिक संख्या में कार्य वीजा मिलते हैं, मुख्य रूप से आईटी क्षेत्र के लिए। यह क्षेत्र अपने राजस्व के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए यूएस-आधारित ग्राहकों पर भी निर्भर करता है।

ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले नाराज हुए एलन मस्क

डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले ही उद्योगपति एलन मस्क बेहद नाराज है। दरअसल, यह नाराजगी डोनाल्ड ट्रंप के पुराने करीबियों और इस चुनाव में बेहद अहम भूमिका निभाने वाले एलन मस्क की बढ़ती ताकत के बाद उभरी है। पांच नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद एलन मस्क दुनिया के गैर-निर्वाचित सबसे ताकतवर व्यक्ति बनकर उभरे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कैबिनेट नियुक्तियों पर एलन मस्क और ट्रंप के काफी लंबे समय से सलाहकार बोरिस एप्सटेन के बीच विवाद छिड़ गया है।

शेयर मार्केट में नहीं होगी ट्रेडिंग, किस वजह से बंद है बाजार?

परिवहन विशेष न्यूज

आज महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। ऐसे में शेयर मार्केट के कई निवेशकों के मन में उलझन है कि आज बाजार खुला रहेगा या बंद। उनकी जानकारी के लिए बता दें कि आज शेयर मार्केट बंद है। बीएसई और एनएसई पर कोई ट्रेडिंग नहीं होगी। महाराष्ट्र में आज स्कूल-कॉलेज के साथ बैंक भी बंद रहेंगे। शराब की दुकानें भी नहीं खुलेंगी।

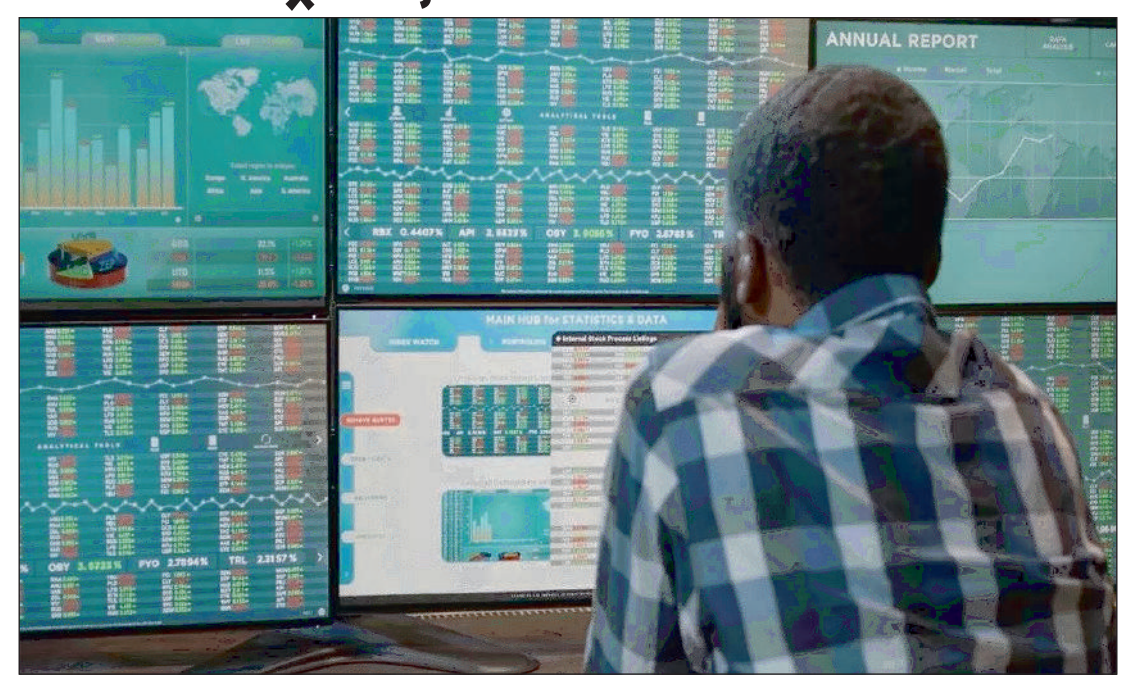

नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार आज यानी बुधवार (20 नवंबर 2024) को बंद रहेगा। शेयर बाजार शनिवार-रविवार के साप्ताहिक अवकाश के अलावा त्योहार या कुछ अन्य खास मौकों पर ही बंद रहता है। बुधवार की छुट्टी की बात करें, तो आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की वोटिंग है। शेयर मार्केट से जुड़े ज्यादातर कामकाज मुंबई से ही होते हैं। इसलिए आज बीएसई और एनएसई, दोनों में ट्रेडिंग नहीं होगी।

दोनों ही एक्सचेंजों- बीएसई और एनएसई ने इस बात की आधिकारिक जानकारी पहले ही दे दी थी। करेंसी मार्केट और कमोडिटी एक्सचेंज पर भी ट्रेडिंग नहीं होगी। इसका मतलब की मुद्रा और सोने-चांदी के भाव भी अपडेट नहीं होंगे।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और नतीजे

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए आज यानी 20 नवंबर को वोट डाले जा रहे हैं। राज्य की 288 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसके लिए चुनाव प्रचार का दौर सोमवार (18 नवंबर 2024) की देर शाम थम गया था। आज महाराष्ट्र में बैंक और स्कूल भी बंद हैं। शराब की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी और उसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे।

NSE ने जारी किया नोटिफिकेशन

NSE ने महाराष्ट्र विधानसभा के मौके पर शेयर बाजार बंद रहने की जानकारी 8 नवंबर को दी थी। उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें कहा गया था कि एक्सचेंज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की वजह से बुधवार, 20 नवंबर, 2024 को बंद रहेगा। इस दिन कोई कारोबार नहीं होगा।

BSE और NSE पर इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव और SLB सेगमेंट में ट्रेडिंग नहीं होगी। करेंसी डेरिवेटिव्स सेगमेंट में भी कारोबार बंद रहेगा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) और नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज (NCDEX) सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच बंद रहेंगे।

नंवबर में कितने दिन बंद रहा बाजार?

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की छुट्टी के बाद शेयर मार्केट में नवंबर के दौरान अब कोई अन्य अवकाश नहीं रहेगा। नवंबर में शेयर मार्केट अब सिर्फ शनिवार-रविवार के साप्ताहिक अवकाश पर ही बंद रहेगा। नवंबर में शेयर मार्केट में कुल 3 दिन छुट्टियां थीं।

1 नवंबर को दीवाली की छुट्टी थी। शेयर बाजार शाम को मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए खुला था। इस दौरान सिर्फ 1 घंटे के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग हुई थी। 15 नवंबर के दिन गुरुनानक जयंती के अवसर पर शेयर मार्केट की छुट्टी थी। अब शेयर बाजार आज यानी 20 नवंबर को बंद है।

खुदरा महंगाई दर के आधार पर ब्याज दर में कटौती पर उठ रहे सवाल, क्या बदलनी चाहिए परंपरा?

परिवहन विशेष न्यूज

भारत में आरबीआई नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करते समय खुदरा महंगाई को सबसे अधिक अहमियत देता है। लेकिन अब इस फॉर्मूले पर केंद्रीय मंत्री और आर्थिक जानकार सवाल उठा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्याज दर सस्ती करने की वकालत की है। कई देशों में ब्याज दर तय करने के लिए इस्तेमाल होने वाली महंगाई दर से खाद्य वस्तुएं और ऊर्जा की कीमतों को हटा दिया जाता है।

नई दिल्ली। पहले वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से ब्याज दरों में कटौती की वकालत को अगले महीने मौद्रिक नीति कमेटी की बैठक में आरबीआई कितनी गंभीरता से लेता है, यह तो अभी कहना मुमकिन नहीं दिख रहा है। लेकिन, इस बात पर बहस जरूर शुरू हो गई है कि खुदरा महंगाई दर के आधार पर ब्याज दरों में कटौती का फैसला लिया जाना कहां तक जायज है।

वित्त वर्ष 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण में भी इस बात को लेकर सवाल उठाया गया था। सर्वेक्षण में कहा गया था कि खुदरा महंगाई दर में खाद्य वस्तुओं के साथ ऊर्जा की महंगाई दर भी शामिल होती है जबकि ब्याज दर का निर्धारण सिर्फ कोर (प्रमुख) महंगाई दर के आधार पर होना चाहिए। अमेरिका, यूरोप व जापान में भी बैंक दर तय करने के लिए इस्तेमाल होने वाली महंगाई दर खाद्य वस्तुएं और ऊर्जा की कीमतों को हटाकर तय की जाती है।

खाद्य वस्तुओं की महंगाई किस वजह से बढ़ती है?

प्रख्यात अर्थशास्त्री एवं भारत के पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद् टीसीए अनंत वर्तमान खुदरा महंगाई दर के आधार पर बैंक दरों को तय करने के पक्ष में नहीं दिखते हैं। उनका मानना है कि खाद्य वस्तुओं की कीमतें अक्सर सप्लाई की तंगी से बढ़ती है और बाकी की वस्तुओं की मांग बढ़ने से अगर कीमत पर दबाव आता है तो उससे मौद्रिक नीति के जरिए निपटा जा सकता है।

गत सोमवार को वित्त मंत्री भी इस बात का हवाला दे रही थी कि आलू, प्याज और टमाटर की वजह से खुदरा महंगाई दर अधिक दिख रही है और इन वस्तुओं की कीमतें मौसमी रूप से मांग व आपूर्ति में अंतर होने पर बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि अन्य वस्तुओं की महंगाई दर नियंत्रण में है। अक्टूबर की महंगाई दर 6.2 प्रतिशत हो गई है जो पिछले 14 माह में सबसे अधिक है।

महंगाई अधिक रहने पर आरबीआई ब्याज दरों में कटौती से इसलिए बचता है क्योंकि इससे लोन सस्ता हो जाएगा और अर्थव्यवस्था में अधिक मांग निकलने लगेगी जिससे वस्तुओं की कीमतें और बढ़ने लगेंगी।

सब्जियों के भाव पर ब्याज दर तय करना कितना सही?

अर्थशास्त्री एवं स्वदेशी जागरण मंच के संयोजक अश्विनी महाजन का मानना है कि अगर हम मौसमी आधार पर, जैसा कि सब्जी के दाम में बढ़ोतरी देखा जाता है, ब्याज दर पर फैसला लेते हैं तो यह हमारी बड़ी भूल है। भारत जैसे विकासशील देश में मौद्रिक नीति कमेटी का उद्देश्य देश का आर्थिक विकास, रोजगार का सृजन और गरीब को उत्थान होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि थोक महंगाई दर और खुदरा महंगाई दर में काफी अंतर होता है इसलिए महंगाई दर को ब्याज दर तय करने का आधार बनाया जाना ठीक नहीं है। आठ साल पहले मौद्रिक नीति कमेटी का गठन किया गया था। आरबीआई ने खुदरा महंगाई दर की अधिकतम सीमा छह प्रतिशत और न्यूनतम सीमा दो प्रतिशत तय कर रखा है। चार प्रतिशत से कम खुदरा महंगाई दर को आरबीआई ब्याज दरों में कटौती के लिए उपयुक्त मानता है।

दूसरी तरफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के प्रोफेसर पिनाकी चक्रवर्ती मानते हैं कि सरकार और आरबीआई दोनों ही अपनी-अपनी जगह पर सही है। क्योंकि भारत में ब्याज दर तय करने के लिए महंगाई दर ही एकमात्र इंस्ट्रूमेंट है। भारत का व्यापक आर्थिकी काफी जटिल भी है।

दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ घटने के आसार, क्या ये चिंता की बात है?

घरेलू रेटिंग एजेंसी इक्रा के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि घटकर 6.5 फीसदी रहने के आसार हैं। हालांकि इक्रा ने एजेंसी ने समूचे वित्त वर्ष के लिए वृद्धि दर का अनुमान सात प्रतिशत पर बरकरार रखा है। यह अनुमान ऐसे समय आया है जब शहरी मांग में कमी जैसे कारणों से वृद्धि में मंदी की चिंताएं सता रही हैं।...

नई दिल्ली। पिछली कुछ तिमाहियों में भारत ने शानदार जीडीपी ग्रोथ दर्ज की है। लेकिन, जुलाई-सितंबर तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि घटकर 6.5 प्रतिशत रहने के आसार हैं। घरेलू रेटिंग एजेंसी इक्रा ने इसके लिए भारी बारिश और कमजोर कॉरपोरेट प्रदर्शन को जिम्मेदार बताया है।

हालांकि, इक्रा को वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही (अक्टूबर 2024-मार्च 2025) में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है। इसलिए रेटिंग एजेंसी ने समूचे वित्त वर्ष के लिए वृद्धि दर का अनुमान सात प्रतिशत पर बरकरार रखा है। यह अनुमान और टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब शहरी मांग में कमी जैसे अनेक कारकों के कारण वृद्धि में मंदी की चिंताएं हैं।

RBI का 7.2% ग्रोथ का अनुमान

आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आर्थिक वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जो 2023-24 के 8.2 प्रतिशत से कम है। आरबीआई का कहना है कि जीडीपी थोड़ी कम ज्यादा रह सकती है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर चिंता करने की कोई बात नहीं है। दूसरी तिमाही की आर्थिक गतिविधि के आधिकारिक आंकड़े 30 नवंबर को जारी होने की उम्मीद है। पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में जीडीपी वृद्धि 6.7 प्रतिशत रही थी।

इक्रा ने कहा कि दूसरी तिमाही में गिरावट भारी बारिश और कमजोर कॉरपोरेट प्रदर्शन जैसे कारकों के कारण होगी। उसने कहा, 'हालांकि सरकारी व्यय और खरीफ की बोआई से सकारात्मक रुझान हैं, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र खासकर खनन तथा बिजली में मंदी आने के आसार हैं।'

अच्छे मानसून का मिलेगा फायदा

रेटिंग एजेंसी की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा, 'वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में आम चुनाव के बाद पूंजीगत व्यय में वृद्धि के साथ-साथ प्रमुख खरीफ फसलों की बुआई में अच्छी वृद्धि देखी गई। भारी बारिश के कारण कई क्षेत्रों को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जिससे खनन गतिविधि, बिजली की मांग और खुदरा ग्राहकों की संख्या प्रभावित हुई और व्यापारिक निर्यात में भी कमी आई।'

उन्होंने कहा कि अच्छे मानसून का फायदा आगे मिलेगा तथा खरीफ उत्पादन में वृद्धि तथा जलाशयों के पुनः भरने से ग्रामीण मांग में निरंतर सुधार होने की संभावना है। मुख्य अर्थशास्त्री ने कहा, 'हम निजी उपभोग पर व्यक्तिगत ऋण वृद्धि में मंदी के प्रभाव के साथ-साथ ¨जस की कीमतों और बाह्य मांग पर भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के प्रभाव पर भी नजर रख रहे हैं।'

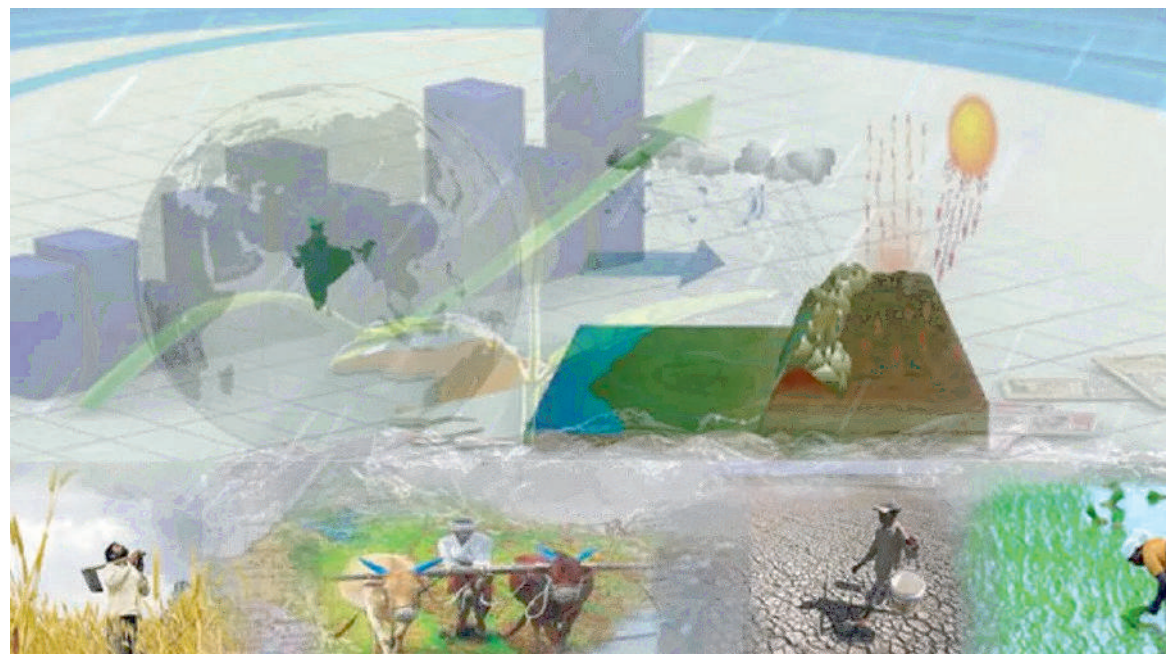

देशभर में 5.8 करोड़ राशन कार्ड फर्जी पाए गए

इसकी आशंका है कि अभी कुछ और फर्जी राशन कार्ड हो सकते हैं। यह आशंका इसलिए है क्योंकि अभी सभी राशन कार्डों का आधार कार्ड से मिलान नहीं किया जा सका है। इसी तरह सभी राशन कार्डों का डिजिटलीकरण भी नहीं किया जा सका है। एक आंकड़े के अनुसार केवाईसी के जरिये कुल पीडीएस लाभार्थियों में से अभी 64 प्रतिशत का ही सत्यापन हो पाया है।

नई दिल्ली। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय की ओर से दी गई यह जानकारी चौंकाने वाली है कि सत्यापन की प्रक्रिया के तहत देशभर में 5.8 करोड़ राशन कार्ड फर्जी पाए गए हैं। राशन कार्डों के सत्यापन के लिए उनका आधार कार्ड से तो मिलान किया ही गया, केवाईसी यानी ग्राहक की पहचान करने की प्रक्रिया का भी पालन किया गया। यह ठीक है कि अपने देश में राशन कार्ड धारकों की संख्या बहुत अधिक है और इसे इससे समझा जा सकता है कि 80 करोड़ लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत मुफ्त राशन दिया जाता है, फिर भी 5.8 करोड़ राशन कार्डों का फर्जी पाया जाना गंभीर बात है।

इसका मतलब है कि कुछ लोग फर्जी राशन कार्ड बनाने का काम करते हैं। इसकी आशंका है कि अभी कुछ और फर्जी राशन कार्ड हो सकते हैं। यह आशंका इसलिए है, क्योंकि अभी सभी राशन कार्डों का आधार कार्ड से मिलान नहीं किया जा सका है। इसी तरह सभी राशन कार्डों का डिजिटलीकरण भी नहीं किया जा सका है। एक आंकड़े के अनुसार केवाईसी के जरिये कुल पीडीएस लाभार्थियों में से अभी 64 प्रतिशत का ही सत्यापन हो पाया है। एक ऐसे समय जब बड़ी संख्या में राशन कार्ड धारकों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, तब यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि पात्र व्यक्ति ही इस सुविधा का लाभ उठा पाएं। इसी क्रम में यह भी देखा जाना चाहिए कि कहीं मुफ्त अनाज पाने के लिए ऐसे लोगों ने राशन कार्ड तो हासिल नहीं कर लिए हैं, जो इसके पात्र नहीं हैं। वास्तव में पीडीएस समेत अन्य सभी योजनाओं में सही लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित की जानी चाहिए, क्योंकि यह किसी से छिपा नहीं कि अन्य योजनाओं में भी अपात्र लोग उनका लाभ उठाने में सफल रहते हैं।

समस्या केवल यह नहीं है कि नकली राशन कार्ड आसानी से बन जाते हैं। समस्या यह भी है कि अब फर्जी आधार कार्ड भी बन जाते हैं। भले ही देर-सबेर फर्जी राशन और आधार कार्डों की पहचान हो जाती हो, लेकिन आखिर ऐसा होना ही क्यों चाहिए कि कोई फर्जी राशन कार्ड या आधार कार्ड हासिल कर ले? बांग्लादेशी और रोहिंग्या भी फर्जी आधार कार्ड बनवा लेते हैं। ध्यान रहे कि कोई एक बार नकली आधार कार्ड बनवा ले तो फिर उसके जरिये अन्य पहचान पत्र बनवाना आसान हो जाता है। इस सिलसिले को रोकना आवश्यक है। इसी के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं, उनका क्रियान्वयन इस तरह किया जाए, जिससे उनका लाभ देश में कहीं पर भी रहने वाले लोग उठा सकें। एक देश-एक राशन कार्ड से ऐसा हो रहा है। जब पीडीएस योजना के तहत ऐसा हो सकता है तो अन्य योजनाओं के तहत भी होना चाहिए, क्योंकि अब नौकरी, व्यापार, शिक्षा के कारण बड़ी संख्या में लोग अपने गांव-शहर से दूर रहने लगे हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिसंबर में ओडिशा की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वर : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिसंबर में 5 दिवसीय दौरे पर ओडिशा आ रही हैं। वह यहां विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्य सचिव और डीजीपी ने समीक्षा बैठक की है।राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू 3 दिसंबर को दोपहर 2:55 बजे वायुसेना के विशेष विमान से दिल्ली हवाईअड्डे से प्रस्थान करेंगी।शाम 5:00 बजे भुवनेश्वर बिजुपटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। प्रोटोकॉल अनुसा में मुख्यमंत्री, मेयर, मुख्य प्रशासनिक सचिव, डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उनका स्वागत करेंगे। राष्ट्रपति शाम 5:30 बजे चन्द्रशेखरपुर हवाईअड्डे से निकलकर नीलाद्रिबिहार स्थित बस्ती जाएंगे। वहां पंडित रघुनाथ मुर्मू की प्रतिमा का अनावरण किया जायेगा। वहां से शाम 6:10 बजे रवाना होकर 6:25 बजे राजभवन पहुंचेगी। रात्रि भोजन एवं विश्राम राजभवन में करेंगे।

4 तारीख को सुबह 9 बजे वह राजभवन से निकलकर एयरपोर्ट जाएंगे। वहां से वह वायुसेना के हेलीकॉप्टर से पुरी जाएंगे। रात 9:45 बजे पुरी पहुंचेगी। सुबह 10:05 बजे प्रभु के दर्शन करेंगे। बाद में गोपबंधु आयुर्वेदिक कॉलेज के 75वें वार्षिकोत्सव में शामिल होंगे। दोपहर 12:00 बजे वहां से रवाना होगी और 12:10 बजे पुरी राजभवन पहुंचेगी। दोपहर 3:40 बजे पुरी राजभवन में उन्हें भारतीय नौसेना द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। वह दोपहर 3.45 बजे ब्लू फ्लैग बीच पर भारतीय नौसेना दिवस में शामिल होंगे। रात में वह पुरी राजभवन में रुकेंगे।

गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए देश भर में अनेक संत, शंकराचार्य, धर्माचार्य और गो प्रेमियों ने अपना गौ रक्षा आन्दोलन तेज कर दिया

तेलंगाना। हैदराबाद वर्तमान ने 7 नवम्बर 1966 के ऐतिहासिक गौरक्षा आन्दोलन के बाद अब 2020 से 2024 में गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए देश भर में अनेक संत, शंकराचार्य, धर्माचार्य और गो प्रेमियों ने अपना गौ रक्षा आन्दोलन तेज कर दिया है ।

वर्तमान में भाजपा की केंद्र सरकार और राजधानी में प्रधान मंत्री भवन में गाय पालने वाले गौ प्रेमी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को गौ प्रेमी बड़ी आसा की नजर से देख रहे है । सबका मानना है प्रधान मंत्री मोदी जी के इसी कार्यकाल में गौ माता को उसका सदियों पूर्व छीना (अब्ध्या) जीवित रहने का हक मिल जाएगा । वहीं तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी जी भी गौ माता की पूजा, सेवा कर वोट डालने गए और तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद पर आसीन है । उनसे भी तेलंगाना के गौ प्रेमियों को बड़ी आसा बनी हुई है देशभर में पिछले दो दशक से भी अधिक समय से गौरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत सर्वदलीय गौरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयपाल सिंह नयाल सनातनी जी द्वारा आगामी 15 दिसम्बर को हैदराबाद, नेकलस रोड पर श्री दक्षिणेश्वर केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट मेढ़चल और सर्वदलीय गौरक्षा मंच के संयुक्त तत्वाधान में 5 K RUN for Gau Mata का भव्य आयोजन रखा है । जिसमें लगभग 2 हजार गौ प्रेमी गौवंश और पर्यावरण की रक्षा का संदेश देने दौड़ेंगे । सबसे

अच्छी बात यह है कि इस गौ पर्यावरण रक्षा जन जागरण दौड़ में माताएं ज्यादा भाग ले रही है । इस दौड़ की हरी झंडी दिखा कर शुरुवात करने के लिए आज आयोजन समिति के लोग भाजपा के सांसद आदरणीय श्री इंटेल राजेंद्र गारू (मेडचल, मलकाजीगिरी,सांसद महोदय) से मिले । सांसद महोदय ने स्वास्थ रक्षा, पर्यावरण रक्षा और गौरक्षा का संदेश देने वाले इस पवित्र कार्यक्रम की भूरी - भूरी प्रशंसा की, आयोजकों का सम्मान किया और अपना पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया।

अकेले पड़ते बुजुर्गों की बढ़ती मुश्किलें....

भारत में पहले से कहीं ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं। उनमें से ज़्यादातर के पास सामाजिक सुरक्षा बहुत कम है और वे स्वास्थ्य सेवा का ख़र्च नहीं उठा सकते। जबकि सरकार उन्हें देखभाल प्रदान करने के लिए तैयार नहीं दिखती। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, भोजन और आश्रय की बुनियादी ज़रूरतें, आय सुरक्षा और सामाजिक देखभाल की आवश्यकता है। बुज़ुर्ग जनसंख्या से जुड़ी अनेक योजनाएँ भी हैं, लेकिन लोग इनसे अनजान हैं या इनसे जुडना उन्हें बोझिल लगता है।

-डॉ सत्यवान सौरभ

देश के वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से वरिष्ठ नागरिक गंभीर आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनकी कोई नियमित आय नहीं है, पेंशन या सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं तक उनकी पहुँच सुलभ नहीं है। बुजुर्गों की सामाजिक ज़रूरतें क्या हैं? ये ज़रूरतें सेहत के लिए ज़रूरी हैं, जिनमें परिवार और दोस्तों के साथ सम्बंध, सार्थक गतिविधियों में भागीदारी और स्वायत्तता और गरिमा का संरक्षण शामिल है। इन ज़रूरतों को सम्बोधित करना सिर्फ़ फ़ायदेमंद ही नहीं है; यह हमारी वृद्ध आबादी के स्वास्थ्य और ख़ुशी के लिए भी ज़रूरी है। वृद्धों की सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करना एक नाज़ुक पौधे की देखभाल करने जैसा है। उन्हें खिलने के लिए सावधानीपूर्वक ध्यान, निरंतर देखभाल और पोषण देने वाले वातावरण की आवश्यकता होती है। आखिरकार, सामाजिक ज़रूरतें सिर्फ़ मानवीय संपर्क की बुनियादी ज़रूरतों से कहीं ज़्यादा हैं। वे किसी व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य का आधार बनती हैं, जो शारीरिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्थिरता दोनों को प्रभावित करती हैं।

बुजुर्गों (60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति) की संख्या 2011 में 100 मिलियन से बढ़कर 2036 में 230 मिलियन हो जाएगी। 2050 तक, बुजुर्गों की आबादी कुल आबादी का लगभग पाँचवाँ हिस्सा होने की उम्मीद है। इससे भारत में बुजुर्गों की आबादी का कल्याण एक आसन्न आवश्यकता बन जाती है। बुजुर्गों की आर्थिक कमज़ोरी जैसे कि अनौपचारिक क्षेत्र के बड़े कार्यबल में पेंशन कवरेज का अभाव है। (भारत में 80% से अधिक कार्यबल अनौपचारिक है) स्वास्थ्य सेवा की बढ़ती लागत और सीमित बचत वित्तीय चुनौतियों को बढ़ाती है। प्रवास और बदलती संरचनाओं के कारण परिवार की सहायता प्रणाली कमज़ोर हो रही है। पेंशन कवरेज का विस्तार करें, किफायती स्वास्थ्य बीमा शुरू करें (आयुष्मान भारत योजना का विस्तार सभी बुजुर्गों के लिए एक अच्छा क़दम है), वरिष्ठ नागरिकों के लिए निवेश विकल्प बनाएँ और रिवर्स मॉर्गेज को बढ़ावा दें।

वरिष्ठ नागरिक समाज में अलगाव की स्थिति से भी त्रस्त हैं। उनमें सामाजिक संपर्कों की कमी के कारण अकेलापन बना रहता है। उनको अपनी संपत्ति की सुरक्षा और अपने साथ होने वाले अपराधों से बचाव की भी ज़रूरत होती है। वरिष्ठ नागरिकों, खासकर अकेले रहने वाले व्यक्तियों, के साथ उनकी संपत्ति से जुड़े और उनके साथ होने वाले अपराधों के समाचार आते रहते हैं। संयुक्त परिवारों और प्रवास में कमी के कारण कई बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं, जिससे अवसाद और चिंता होती है। सांस्कृतिक बदलावों ने अंतर-पीढ़ीगत सम्बंधों को भी प्रभावित किया है। बुजुर्गों के प्रति पारंपरिक सम्मान और श्रद्धा, जो कभी भारतीय समाज की आधारशिला हुआ करती थी, अब सूक्ष्म बदलावों से गुज़र रही है। बुजुर्ग महिलाएँ, ख़ास तौर पर विधवाएँ, अक्सर सामाजिक अलगाव के ज़्यादा गंभीर रूपों का सामना करती हैं। प्रौद्योगिकी के साथ चुनौतियाँ डिजिटल विभाजन बुजुर्गों को और अलग-थलग कर देता है। सामुदायिक जुड़ाव कार्यक्रम, वरिष्ठ क्लब, अंतर-पीढ़ी कार्यक्रम और स्वयंसेवा के अवसर हैं।

बुजुर्गों के कल्याण के लिए उपाय जैसे कि बुनियादी ढाँचा विकास, आयु-अनुकूल स्थान, सुलभ परिवहन और वृद्धावस्था स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करेगा, जिससे गतिशीलता, स्वतंत्रता और सामाजिक संपर्क में सुधार होगा। ऑनलाइन सेवाओं तक पहुँचने के लिए बुजुर्गों के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम। मानवीय संपर्क बनाए रखने के लिए टेलीमेडिसिन और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली। सरकार, गैर सरकारी संगठनों (एजवेल फ़ाउंडेशन), निजी क्षेत्र और स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग ज़रूरी है। धार्मिक संस्थाएँ सामाजिक और आध्यात्मिक सहायता प्रदान कर सकती हैं। अवसाद और चिंता से निपटने के लिए सुलभ परामर्श, सहायता समूह और गतिविधियाँ। पारिवारिक सहायता को मज़बूत करना और परामर्श और अंतर-पीढ़ी कार्यक्रमों के माध्यम से पारिवारिक बंधन को बढ़ावा देना। बहु-पीढ़ी के परिवारों के लिए प्रोत्साहन जैसे कि स्विट्जरलैंड की टाइम बैंक पहल की नकल। इस पहल के तहत, युवा पीढ़ी वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करके 'समय' बचाना शुरू करती है। बाद में, वे बचाए गए 'समय' का उपयोग तब कर सकते हैं जब वे बूढ़े हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं या उन्हें किसी की ज़रूरत होती है जो उनकी देखभाल करे। इस पहल को भारतीय व्यवस्था में लागू किया जाना चाहिए। भारत को भविष्य में सेवानिवृत्ति की आयु को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाना चाहिए ताकि युवा पीढ़ी के अवसरों को जोखिम में न डाला जा सके।

बुजुर्ग आबादी के लिए सरकारी योजनाएँ जैसे वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2011, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, वरिष्ठ देखभाल एजिंग ग्रोथ इंजन पहल और पोर्टल इसे सुचारू और मज़बूत बनाएंगे। बुजुर्ग भारत अपने बुजुर्गों के लिए एक देखभाल करने वाला भारत भी हो सकता है। दोनों पहलुओं (वित्तीय और साथ ही सामाजिक कमजोरियों) को सम्बोधित करने वाली समावेशी, सुलभ और व्यापक कल्याण योजनाएँ बनाकर, भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसकी बुजुर्ग आबादी सम्मान, सुरक्षा और सामाजिक जुड़ाव के साथ आगे बढ़े। वृद्धों की सामाजिक ज़रूरतों को सम्बोधित करना उनके समग्र कल्याण के लिए महत्त्वपूर्ण है। चाहे वह सार्थक सम्बंधों को बढ़ावा देना हो, नियमित सामाजिक संपर्कों को प्रोत्साहित करना हो, स्वतंत्रता को बढ़ावा देना हो, या पेशेवर सहायता और सेवाएँ प्रदान करना हो, प्रत्येक तत्व सफल बुढ़ापे को सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

जबकि सामाजिक अलगाव और सामाजिक भागीदारी में बाधाओं जैसी चुनौतियाँ मौजूद हैं, उन्हें व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामुदायिक और पेशेवर सहायता से दूर किया जा सकता है। जैसा कि हम अपनी वृद्ध आबादी की सेवा करना जारी रखते हैं, आइए याद रखें कि उनकी सामाजिक ज़रूरतें उनकी शारीरिक ज़रूरतों जितनी ही महत्त्वपूर्ण हैं। आखिरकार, एक अच्छी तरह से जीया गया जीवन एक अच्छी तरह से जुड़ा हुआ जीवन है।

सीसामऊ उप चुनाव : सपाईयों और भाजपाइयों का हंगामा, मनोज सिंह का धरना, दो दरोगा सस्पेंड

- कड़ी सुरक्षा के बाद भी हंगामा पूर्ण रहा सीसामऊ का उपचुनाव
- सपा ने लगाया वोट डालने से रोकने का आरोप और धरने पर बैठे भाजपाई
- आईडी चेक करने पर चुनाव आयोग ने दो दरोगाओं को किया निलंबित
- मतदान केंद्रों पर भीड़ से नजर आई भाजपा और सपा में कांटे की टक्कर
- कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच छिटपुट घटनाओं को छोड़कर सीसामऊ में संपन्न हुआ शांतिपूर्ण मतदान

सुनील बाजपेई

कानपुर। यहां बेहद कड़ी सुरक्षा में आरोप प्रत्यारोप और हंगामे के बीच सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव संपन्न हुआ। इस दौरान समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक दूसरे पर आरोप लगाकर कई जगह हंगामा भी किया। मतदान के दौरान ही जीआईसी मतदान केंद्र पर भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी की कार पर पथराव करने का भी आरोप लगाया गया।

प्रत्याशी सुरेश अवस्थी की कार पर पत्थर फेक जाने और फर्जी वोटिंग का आरोप लगाकर भाजपाई धरने पर भी बैठे।

वरिष्ठ भाजपा नेता मनोज सिंह दबौली ने कहा कि सपा के गुंडों ने फर्जी मतदान किया। जिसका जमकर विरोध भी किया गया। वरिष्ठ भाजपा नेता मनोज सिंह ने कहा कि सपा वालों ने हारने के डर से ही फर्जी वोटिंग का सहारा लिया। जबकि सीसामऊ सीट पर भाजपा की जीत होने से कोई ताकत कदापि नहीं रोक सकती। इस दौरान पुलिस पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने मतदान से रोकने का भी आरोप लगाया। इसी के साथ चुनाव आयोग ने आईडी चेक करने के आरोप में दो दरोगाओं को सस्पेंड भी कर दिया।

कुल मिलाकर यहां शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पुलिस फोर्स को भी भारी मशक्कत करनी पड़ी। आज 20 नवंबर को हुए मतदान के दौरान कानपुर की सीसामऊ सीट पर उपचुनाव के लिए चमनगंज, बेकनगंज, फहीमाबाद, ग्वालटोली, नाला रोड समेत मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटरों ने हंगामा किया।

इस दौरान जीआईसी मतदान केंद्र पहुंची सपा प्रत्याशी और इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी ने बूथ एजेंट को पीटने का आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी तबीयत से पिटाई की गई है। बूट-बूट मारा गया है। नसीम सोलंकी के बाद जीआईसी में भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी भी समर्थकों के साथ पहुंचे। इसी बीच उनकी कार में पत्थर फेंकने का भी आरोप लगाया गया। इस बीच पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील रहा।

ग्वालटोली के मकबरा मोहल्ले में सपा की महासचिव नीलम रोमिला सिंह की पुलिस से झड़प हो गई। उन्होंने कहा- हिंदू बहुल इलाकों में सामान्य तरीके से मतदान हो रहा है, जबकि यहां पुलिस दबिश दे रही है। लोगों को डरा रही है।

सीसामऊ विधानसभा के 2.71 लाख मतदाताओं के वोट डालने की व्यवस्था 275 वोटो पर की गई थी। मतदान केंद्रों पर आज शाम 5:00 बजे तक के लिए बुधवार सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी।समाचार लिखे जाने तक मतदान का आंकड़ा लगभग 50% के आसपास पहुंच चुका था। वही कड़ी सुरक्षा रखने के तहत 1200 मतदान कर्मियोंको भी तैनात किया गया था।

अवगत कराते चलें कि आज 20 नवंबर को कराया गया सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव पांच प्रत्याशियों के बीच हुआ है, जिनमें भाजपा से सुरेश अवस्थी, सपा से नसीम सोलंकी, बसपा से वीरेंद्र कुमार, सभी जन पार्टी से अशोक पासवान हैं। जबकि कृष्ण कुमार यादव निर्दलीय उम्मीदवार हैं।

सुधर रहे भारत-चीन के रिश्ते, रक्षा मंत्री डोंग जून से मिले राजनाथ सिंह; पढ़ें किन मुद्दों पर हुई बातचीत

राजनाथ सिंह ने लाओस में चीन के रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात की। आधिकारिक बैठक में राजनाथ सिंह चीनी रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून से मिले। इससे पहले विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की थी। राजनाथ सिंह ने कहा है कि वियनतियाने में चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून के साथ बहुत ही उत्पादक बैठक हुई है।

नई दिल्ली। भारत और चीन ने सैन्य विवाद को सुलझा कर द्विपक्षीय रिश्तों को सामान्य बनाने की दिशा में अपनी कोशिश तेज कर दी है। बुधवार को दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की अगुवाई में आधिकारिक बैठक लाओस में हुई है। इस बैठक को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेहद रचनात्मक करार दिया है और आपसी भरोसे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही है।

चीनी रत्रा मंत्री से राजनाथ सिंह की मुलाकात

राजनाथ सिंह की चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून के साथ यह मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई बैठक के 48 घंटे बाद हुई है। जयशंकर और वांग यी के रियो डी जनेरो में बैठक हुई थी जिसमें कैलास मानसरोवर यात्रा की शुरुआत करने, दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू करने जैसे मुद्दों पर बात हुई थी।

भारत-चीन के बीच सुधर रहे हालात

भारत और चीन के बीच स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा के कुछ हिस्सों पर सैन्य विवाद अप्रैल, 2020 से चल रहा था। इसे सुलझाने में अंतिम सफलता 21 अक्टूबर, 2024 को पीएम नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच हुई हुई बैठक में मिली। उसके बाद जिन स्थलों पर दोनों देशों के सैनिक अभी तक तैनात थे, उन्हें हटा लिया गया है और दोनों तरफ की सेनाएं तनाव शुरू होने से पहले वाली स्थिति में करने लगी हैं।

विदेश मंत्री जयशंकर ने भी कहा है कि शीर्ष नेताओं के बीच सहमति के आधार पर अब संतोषजनक कदम उठाये जा रहे हैं। इस क्रम में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक अहम माना जा रहा है। अब दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के स्थाई हल के लिए नामित विशेष प्रतिनिधियों के बीच बैठक शुरू होने की संभावना है।

क्या बोले राजनाथ सिंह?

राजनाथ सिंह ने कहा है कि वियनतियाने में चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून के साथ बहुत ही उत्पादक बैठक हुई है। आपसी भरोसा व समझ बढ़ाने के लिए हमारे बीच रोडमैप बनाने की सहमति बनी है।

जिन्दगी का हिसाब

आईए जिन्दगी का कुछ हिसाब करते हैं,
पल-पल बीत गया उसकी बात करते हैं।
कोई नया मिल गया तो मुलाकात करते हैं,
जो कोई बिछड़ गया उसको याद करते हैं!
ए जिन्दगी तुझसे हम कोई बात करते हैं।

आईए जिन्दगी का कुछ हिसाब करते हैं,
पल-पल बीत गया उसकी बात करते हैं।
कोई हमसे रूठ गया उसकी बात करते हैं,
क्यों? कोई बिछड़ गया शिकायत करते हैं!
ईश्वर उससे मिला दे हम फ़रियाद करते हैं।

आईए जिन्दगी का कुछ हिसाब करते हैं,
पल-पल बीत गया उसकी बात करते हैं।
धैर्य, हौसला, साहस और हिम्मत की हमने,
न जाने कैसे संघर्षों से जिंदगी जी हैं हमने!
दुनिया की नफरतों से भी प्रेरणा ली हमने।

आईए जिन्दगी का कुछ हिसाब करते हैं,
पल-पल बीत गया उसकी बात करते हैं।

संजय एम. तराणेकर

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023